RNI No. : CHHHIN/2011/40280

पाक्षिक पत्रिका

छत्तीसगढ़ आजतक

वर्ष : 13 • अंक : 05 • नवंबर - प्रथम 2023 • मूल्य : 40/-

चुनावी समर 2023

भाजपा की कमज़ोर नब्ज़

अडानी

18 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने क्यों उतार दिए अपने सांसद?

38 भाजपा में शामिल होते ही धूल जाते हैं दाग!

36 डॉ. खूबचंद बघेल का निर्वाचन क्षेत्र फिर से सुर्खियों में

अब अपने घर में मनेगी दीपावली
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महाऑफर
CHOUHAN GROUP
जी.एस.टी. फ्री
रजिस्ट्री फ्री
एक साल का मेंटेनेंस फ्री
5 लाख
की अतिरिक्त छूट
प्रथम 24 फ्लेट की बुकिंग पर
पहले आएं... पहले पाएं...
READY FOR POSSESSION
CHOUHAN Town
E TYPE PREMIUM FLAT
PREMIUM 3 BHK FLAT
BESIDE SHANKRACHARYA ENGINEERING COLLEGE, NEAR T.I. MALL, JUNWANI, BHILAI
Chouhan Green Valley
जुनवानी रोड, भिलाई
READY FOR POSSESSION
बुकिंग प्रारंभ
ROW HOUSE BUNGALOW
Deepak Advertisers
विशेष छूट
2 BHK ₹14.99* Lakh
2 BHK 1 लाख की छूट
3 BHK 2 लाख की छूट
3 BHK ₹26.99* Lakh
4 BHK ₹36.99* Lakh
MEMBER OF CREDAI
CHOUHAN GROUP BOOKING OFFICE
4th Floor, Chouhan Park View Commercial, Beside Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Junwani Road, Bhilai
9229253705, 9229200578, 9109104783, 9229296085, 7222909449, 9229200574, 9109104004

Website : www.chhattisgarhaajtak.com
E-Mail : cg.aajtak@gmail.com

पाक्षिक पत्रिका

छत्तीसगढ़ आजतक

वर्ष : 13 ● अंक : 05 ● नवंबर - प्रथम 2023

संपादक	:	लखन लाल
सलाहकार संपादक	:	सादात अनवर
कार्यकारी संपादक	:	दीपक रंजन दास
विशेष प्रतिनिधि	:	मंजुला कौशिक, आर.के. वर्मा विक्रम जनबंधु
कानूनी सलाहकार	:	गिरीशचंद्र शर्मा
प्रबंध संपादक	:	डॉ. डी.पी. देशमुख
सरगुजा प्रभारी	:	अमरेश्वर दुबे
विशेष संवाददाता	:	पी. मोहन

प्रतिनिधि :-

रायपुर	:	भूपेन्द्र वर्मा
दुर्ग	:	रामशरण कौशिक
भिलाई	:	सतीशदास वैष्णव
भिलाई - 3	:	श्यामलाल साहू
राजनांदगांव	:	राहुल गौतम
कबीरधाम	:	सुरेश प्रसाद गुप्ता
कोरबा	:	अजय कुमार
जांजगीर-चांपा	:	समयदास अविनाशी
कटघोरा	:	विकास जायसवाल
कोण्डागांव	:	सुरेश पाटले
नारायणपुर	:	नरेन्द्र देवांगन
जगदलपुर	:	हेमंत कश्यप
धमतरी	:	जियाऊल हुसैनी
बालोद	:	अरमान खान 'अश्क'
बलौदाबाजार	:	संतोष यादव
तिल्दा-नेवरा	:	दिलीप वर्मा
बोड़ला	:	नवलकिशोर श्रीवास्तव
अंबिकापुर	:	धनंजय दुबे
मनेन्द्रगढ़	:	मनप्रीत सिंह साहनी
रामानुजगंज	:	विकास केसरी
वाड्रफनगर	:	प्रदीप जायसवाल
दल्लीराजहरा	:	कमल शर्मा
गुंडरदेही	:	रमेश चांडक
पाटन	:	उमाशंकर वर्मा
उतई	:	सतीश पारख
बलरामपुर	:	नितेश श्रीवास्तव
दंतेवाड़ा	:	देवकरण बुरड
बिलासपुर	:	सत्येन्द्र प्रकाश सूर्यवंशी
महासमुंद	:	मनोज शंकर

संपादकीय, विज्ञापन, प्रसार कार्यालय
ब्लॉक बी-1, प्रथम तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.)
भिलाई कार्यालय : जी.ई. रोड, कोसानगर, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
संपर्क : 99261 80287, 88895 70726

प्रसार व विज्ञापन विभाग
पत्रिका की सदस्यता व विज्ञापन के लिए संपर्क करें
भूपेन्द्र वर्मा-8889570726, गजेन्द्र-7999139990,
दिनेश यादव-6264374105

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- लखन लाल के लिए सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ब्लॉक बी-1 प्रथम तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित, **संपादक - लखन लाल**

सर्वाधिक सुरक्षित : किसी भी रूप से सामाग्री की नकल प्रतिबंधित है. सभी विवादों का निपटारा रायपुर न्यायालय में होगा.

10

आवरण - कथा

कमजोर नब्ज अडाणी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथित दोस्त गौतम अडाणी पर हुई हर चोट पर भाजपा तिलमिला जाती है. भाजपा शासन के 15 सालों में छत्तीसगढ़ अडाणी की कंपनियों के लिए चारागाह बना हुआ था. पर भूपेश बघेल की सरकार आते ही उसका खेल यहां से खत्म होने लगा. पहले उसके हाथ से बस्तर की खदान गई और फिर हसदेव वनक्षेत्र में आदिवासियों के विरोध...

08

तरकश में कई तीर...

वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस धारदार अंदाज में और ठोस मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है, लेकिन बस्तर संभाग के मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस के पास मुद्दों की भरमार है. नगरनार स्टील प्लांट...

18

क्यों उतारे सांसद...

भारतीय जनता पार्टी ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर एक ऐसा दांव खेला है जिससे राजनीतिक विश्लेषक तक चकित हैं. पार्टी ने इन राज्यों में अब तक अपने 21 सांसदों को चुनाव मैदान में...

04	कृषि	:	लाखों में होगी किसान की कमाई...
20	चुनाव समर	:	वीवीआईपी 6 सीटों पर घमासान...
24	सियासत	:	बालोद जिला: तीनों सीटों पर घमासान...
30	मुद्दा	:	कर्जमाफी: भूपेश से भिड़े रमन...
38	चुनाव समर	:	शामिल होते ही धूल जाते हैं दाग...

हेट स्पीच के भरोसे भाजपा

लखन लाल

छत्तीसगढ़ में भाजपा हेट स्पीच के भरोसे है. यहां तमाम ऐसी बातें कही जा रही हैं, जो किसी भी राष्ट्रीय दल को शोभा नहीं देता. बिगड़े बोलों के ऐसे किस्से स्वयं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से शुरू होते हैं. गृह मंत्री ने कई मौकों पर छत्तीसगढ़ में कहा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को उलटा लटकाकर सीधा किया जाएगा. इसके अर्थ उनके लिए चाहे जो हो, यह सीधे-सीधे धमकी देने, अदालतों और कानून व्यवस्था के दायरे से बाहर निकलकर कही गई बातें हैं. ताज्जुब का विषय यह भी है, कि जिस तरह की बातों के लिए राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, भाजपा के कद्दावर उन सीमाओं को भी बार-बार लांघ रहे हैं. बार-बार देश के प्रथम गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल का नाम जपने वाले उनके आदर्शों को भूलकर मंच से लफ्फाजी करते नजर आते हैं. दूसरा उदाहरण असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का है. हिमंता इससे पहले कांग्रेस में थे. उन पर शारदा चिटफंड घोटाले में प्रतिमाह 20 लाख रुपए का लाभ लेने का आरोप था. भाजपा प्रवेश के साथ ही न केवल उनके खिलाफ जाँच बंद हो गई, बल्कि अब वे शिष्टाचार तक भूल गए हैं. कवर्धा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कि पहले उत्तर प्रदेश में भी बाबर-बाबर सुनाई देता था. मोदी सरकार आते ही बाबर का पत्ता साफ हो गया. कवर्धा में चारों तरफ अकबर-अकबर सुनाई देता है. एक अकबर आता है, तो 100 और अकबर बुला लाता है. यहां से मोहम्मद अकबर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं. 1998, 2003, 2008 और 2018 के चुनाव में वे विधायक निर्वाचित हुए. जोगी और भूपेश बघेल दोनों की सरकार में मंत्री भी रहे. इस बिगड़े बोल के लिए हिमंता को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है. ये हाल है असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री का कि आयोग का नोटिस जारी हो रहा है. साजा से जिस ईश्वर साहू को भाजपा ने टिकट दिया है, उनकी कुल जमा पहचान यही है कि उनके बेटे की कुछ मुसलमानों ने हत्या कर दी थी. यह कोई जातीय हिंसा नहीं, बल्कि मारपीट का एक मामला था जिसे जातीय रूप देने की कोशिश भाजपा और अन्य हिन्दू संगठन घटना के बाद से ही कर रहे थे. केन्द्र सरकार के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ईडी और आईटी से भी दो कदम आगे हैं. वे दावा कर रहे हैं, कि भिलाई से कांग्रेस प्रत्याशी जीत भी गए तो बाद में उन्हें सीट खाली करनी पड़ेगी. प्रश्न यह उठता हैं कि क्या पूर्व कानून मंत्री ईडी के निर्णय को जानते हैं? यह सीधे-सीधे मतदान को प्रभावित करने का मामला बनता है. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल. मांडविया ने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा है, कि जो लोग आज मंत्रियों के पैर छू रहे हैं, भाजपा की सरकार बनने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. चरण स्पर्श करने वालों की लिस्ट भी बन रही है. ऐसा बड़बोलापन एक केन्द्रीय मंत्री को शोभा नहीं देता, जो स्टार प्रचारक हो. जाहिर है कि लगभग 10 साल केन्द्र की सत्ता में रहने के बाद भी उनमें तहजीब नहीं आई है.

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को धमकाते हुए कहा है कि जो लोग आज मंत्रियों के पैर छू रहे हैं, भाजपा की सरकार बनने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जाहिर है कि लगभग 10 साल केन्द्र की सत्ता में रहने के बाद भी उन्हें तहजीब नहीं आई है.

सर्वाधिक शांत प्रदेश की फिजां में सांप्रदायिकता और वैमनस्यता का जहर फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसे छत्तीसगढ़ के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे. इसका करारा जवाब तो मतदान ही हो सकता है.

'उजियारे' की ओर प्रस्थान कर चला 'दीपक'

सुप्रसिद्ध रंगगर्मी लोककला साधक दीपक चंद्राकर नहीं रहे. 20 अक्टूबर 2023 को हृदयघात से उनका निधन हो गया. पर 69 वर्ष की आयु में अलविदा कह गए दीपक ने 'लोकरंग' के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का उजियारा पूरी दुनिया में फैला दिया. स्थूल रूप से अनुपस्थित होने के बावजूद उनकी मौजूदगी का अहसास लोकमंच पर हमेशा होता रहेगा.

» डॉ. डीपी देशमुख

छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न प्रांतों से लेकर राजधानी दिल्ली तक छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को पूरे ठसन और धमक के साथ प्रस्तुत करने वाले दीपक चंद्राकर की रिक्तता को कभी पूरा नहीं किया जा सकता. पर उनकी थाती को संभाल रहे उनके द्वारा प्रशिक्षित सैकड़ों कलाकार उनके कार्यों को आगे बढ़ाते रहेंगे. बातचीत के दौरान वे अक्सर कहा करते थे कि अपने पिता दाऊ उजियार सिंह चंद्राकर की वे छाया मात्र हैं. इसलिए उन्होंने अपने घर का नाम भी "उजियार" रखा है. दाऊ उजियार सिंह एक प्रसिद्ध तबला वादक थे. उन्हीं की प्रेरणा से पुत्र दीपक ने छत्तीसगढ़ी लोककला को नया आयाम दिया.

दीपक ने आजीवन अपने कृतियों का श्रेय अपने गुरुओं को दिया. वे प्रत्येक उस व्यक्ति को अपने आगे रखकर चलते थे जिनसे उन्होंने कुछ न कुछ सीखा. इनमें प्रमुख है "सोनहा बिहान" के संचालक दाऊ महासिंह चंद्राकर. दीपक उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे. इसके अलावा उनकी कृतियों पर प्रसिद्ध लोक नाट्य निर्देशक रामहृदय तिवारी की अमिट छाप रही है. दीपक एवं रामहृदय जी की जोड़ी ने अनेक प्रभावी नाटकों, टेली फिल्म, लघु फिल्म एवं वृत्तचित्रों का मंचन और निर्माण किया.

दीपक ने आजीवन अपने दिवंगत पिता की यादों को लोककला और लोकसंस्कृति की सात्विक और पवित्रता का निर्वहन करते हुए संजोए रखा. 1993 में दीपक ने इसी उद्देश्य के साथ "लोकरंग" का गठन किया. लोकरंग के माध्यम से सैकड़ों कलाकर दीक्षित और प्रशिक्षित हुए. वे एक अच्छे संगठनकर्ता, अनुशासित प्रशिक्षक, सफल कृषक और विनम्र सेवाभावी इंसान थे. 'यथा नाम तथा गुण' की कहावत उनके लिए शत-प्रतिशत चरितार्थ होती है. दीपक के शाब्दिक अर्थ को सही अर्थों में आलोकित करने वाले दीपक चंद्राकर के लिये यह श्लोक उचित प्रतीत होता है-

शुभम् करोति कल्याणम् आरोग्यम् धन संपदा।
शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते॥
दीपो ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः ।
दीपो हरतु मे पापं संध्यादीप नमोऽस्तुते ॥

हिंदी में अर्थ: मै उस दीपक के प्रकाश को नमन करता हूँ जो वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे स्वास्थ्य और धन उनका प्रभाव न केवल लोक कलाकारों बल्कि सामान्य जनों के साथ-साथ परिवार पर भी पड़ा है. उनके पुत्रद्वय विवेक और आनंद अच्छे कृषक और व्यवसायी होने के साथ ही लोककला में रुचि रखते हैं. उनकी अनुपस्थिति में परिवार का पूरा भार उनकी पत्नी विद्यादेवी पर है. अब उनकी स्मृति को संचित कर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उन पर ही है. इसमें लोककला को प्रवाहमान बनाए रखने के साथ ही लोक कलाकारों के पोषण और उनके सृजन को सुरक्षित करने का गुरुभार भी उन पर ही है. इसकी जरूरत इसलिए भी है कि लोकरंग का रंग धूमिल न हो और न ही खंडित हो. उनके बाद उनके कार्यों का विस्तार ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. दीपक रूपी जीवन की बाती तो एक न एक दिन बुझ ही जाती है पर यह संभव नहीं कि लोग उसकी उजास भूल जाएँ. इसीलिये कहा गया है -

एक बाती थरथराती जिंदगी है,
कौन झोंका लूट जाए क्या पता?
काँच की कोमल बहुत चूड़ी बनी है
कि घड़ी कब टूट जाए क्या पता?

अब 'दीपक' के प्रकाश को 'उजियारा' बनाए रखने की जवाबदारी 'लोकरंग' टीम की है.

हजारों में नहीं अब लाखों में होगी किसान की कमाई

- पांच जिलों के 800 एकड़ में हो रही खेती
- बहुवर्षीय पौधों से साल में 3-4 बार उपज
- प्रति एकड़ 80 हजार से एक लाख तक आय
- विश्व में इसका प्रमुख निर्यातक है भारत

» भूपेन्द्र वर्मा

धान की खेती से प्रति एकड़ जहां चार माह के सीजन में बमुश्किल 8 से 10 हजार रुपए की कमाई होती है, वहीं वैकल्पिक फसल प्रति एकड़ होने वाली इस कमाई को कई गुना बढ़ा सकती है. ऐसी ही एक खेती छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के 66 गावों के लगभग 800 एकड़ क्षेत्र में की जा रही है. यह फसल है "लेमन ग्रास" की. औषधीय गुणों से भरपूर लेमनग्रास की फसल से किसान प्रति एकड़ सालाना एक लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं. औषधि, पेय और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में काम आने वाले लेमन ग्रास का भारत सबसे बड़ा निर्यातक भी है.

लेमनग्रास एक औषधीय पौधा है, जो खासकर दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाया जाता है. यह घास जैसा ही दिखता है, बस इसकी लंबाई आम घास से ज्यादा होती है. इसका ज्यादातर उपयोग चाय में अदरक की तरह किया जाता है. इसके अलावा, दवा के रूप में भी लेमनग्रास आयल का उपयोग किया जाता है. इसमें लगभग 75 प्रतिशत सिट्रल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी खुशबू भी नींबू जैसी होती है. लेमन ग्रास तेल का उपयोग सौंदर्य उत्पाद और पेय पदार्थों में किया जाता है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की पहल से किसान इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी.श्रीनिवास राव ने बताया, कि छत्तीसगढ़ में अब किसानों द्वारा सकारात्मक रूप से लेमनग्रास को अपनाया जा रहा है. यह एक बहुवर्षीय फसल है. अर्थात् इसे एक बार लगाकर कई बार फसल काटी जा सकती है.

छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के सीईओ जेएसीएस राव ने बताया कि राज्य के महासमुंद, पेंड्रा, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर तथा बलरामपुर जिलों के 66 ग्रामों के 653 किसानों के लगभग 800 एकड़ में लेमनग्रास की खेती की जा रही है. इससे किसानों को प्रति एकड़ 80,000 रुपए से लेकर एक लाख रुपये तक की आमदनी संभावित है.

विभिन्न जिलों में किसानों को लेमनग्रास की खेती का प्रशिक्षण दिया गया है. उन्हें लेमनग्रास के उत्पादन के साथ ही आसवन द्वारा इसका तेल निकालने का भी प्रशिक्षण दिया गया है. लेमनग्रास की मांग सौन्दर्य उत्पाद और सुगंधित तेल के साथ ही परफ्यूम और हर्बल इंडस्ट्री में भी है. राज्य सरकार के औषधि पादप बोर्ड द्वारा किसानों को लेमनग्रास का पौधा निःशुल्क वितरित किया जा रहा है. वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 800 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में लेमनग्रास की खेती की जा रही है।

लेमन ग्रास का प्रसंस्करण

बाजार में लेमनग्रास तेल की वर्तमान कीमत 800 से 950 रुपये प्रति किग्रा तक है. फसल कटाई कर आसवन यूनिट की सहायता से उसका तेल निकाल लिया जाता

है. इसके बाद तेल बाजार में विक्रय के लिए तैयार हो जाता है. बोर्ड द्वारा मार्केटिंग के लिए भी सुविधा प्रदाय की जाती है, जिससे किसानों को 15 दिनों में ही उपज का पैसा प्राप्त हो जाता है.

इसलिए दुनिया भर में बढ़ी मांग

लेमनग्रास और लेमनग्रास ऑयल की मांग बढ़ने के पीछे कई कारण हैं. इसका उपयोग साधारण स्वास्थ्य को बरकरार रखने के साथ ही अनेक बीमारियों की रोकथाम कर सकता है. कुछ बीमारियों में भी इसे उपयोगी पाया गया है. लेमनग्रास में कई औषधीय गुण होते हैं, जिस वजह से कई आयुर्वेदिक उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन (एनसीबीआई) की रिसर्च के मुताबिक इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी फंगल और सूजन को दूर करने के लिए एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं. ये कई तरह की बीमारियों और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं. लेमनग्रास कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ही पाचन के लिए भी लाभकारी है. यह अपच, गैस्ट्रिक से राहत दिलाकर पेट की अंदरूनी दीवारों को सुरक्षित रखता है. मूत्रवर्धक गुणों के कारण यह किडनी को भी स्वस्थ और पथरियों से मुक्त रखता है.

लेमनग्रास में पाए जाने वाले तत्व कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं. यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे वजन कम करने में भी मदद मिल सकती है. लेमनग्रास में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, बी और सी मौजूद होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं. लेमनग्रास में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं.

इसके अलावा लेमनग्रास का सेवन अनिद्रा, अवसाद, गठिया, दर्द और सूजन को कम कर सकता है. लेमनग्रास में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो न्यूरोडीजेनेरेटिव रोग से बचाव कर सकता है. शोध में लेमनग्रास को तंत्रिका तंत्र का टॉनिक माना गया है. यह अस्थमा, स्ट्रेस और डायबिटीज में भी लाभकारी है.

पड़त भूमि पर खेती

बोर्ड के मुताबिक छत्तीसगढ़ की जलवायु लेमनग्रास की खेती के लिए उपयुक्त पाई गई है. इसकी खेती खाली पड़त भूमि पर की जा सकती है. लेमनग्रास की खेती कई प्रकार की भूमि पर की जा सकती है, जिसमें सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है. इसको एक बार रोपण करने के छह माह बाद ढाई-ढाई माह में फसल ली जा सकती है. लेमनग्रास की बुआई अत्यधिक ठंड तथा गर्मी को छोड़कर साल में कभी भी की जा सकती है. एक एकड़ में रोपण के लिए 16 से 20 हजार पौधों की जरूरत होती है.

शहरी आबादी को मिला इन योजनाओं का लाभ

» राहुल गौतम

- बिजली बिल हाफ का मिला फायदा
- जमीन के छोटे टुकड़ों की रजिस्ट्री शुरू
- पट्टे की जमीन का मिला मालिकाना हक
- भ्रष्टाचार से मुक्ति, घर बैठे मिल रहे दस्तावेज
- कोरोना काल का किया अनोका प्रबंधन

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को आम तौर पर ग्रामीणों और किसानों की सरकार माना जाता है. पर ऐसा नहीं है. भूपेश सरकार ने छोटे-छोटे परिवर्तनों और नवोन्मेष से आम शहरी के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है. बिजली बिल हाफ, छोटे भूखण्डों की रजिस्ट्री, रजिस्ट्री शुल्क में कटौती, जैसे अनेक उपायों से सरकार ने शहरी आबादी को भी लाभान्वित किया है. सरकारी दफ्तरों में शिष्टाचार के रूप में पनप रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों का भी शहरी आबादी को लाभ मिल रहा है.

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने आम लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए कई प्रयास किये हैं. इन्हीं योजनाओं का नतीजा है कि जब कोरोना काल में और उसके ठीक बाद देश भर के छोटे व्यापारी मंदी की मार सह रहे थे, तब भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कभी पटरी से नहीं उतरी. सरकार ने गांव में अंतिम व्यक्ति के हाथ तक पैसा पहुंचाया और वह पैसा घूमकर बाजार पहुंचा. इसके अलावा सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी भी थीं जिसका लाभ सीधे-सीधे शहरी आबादी को मिली.

बिजली बिल हाफ

शहरी आबादी के लिए प्रतिमाह बिजली खपत के प्रथम 400 यूनिट पर शुल्क को आधा कर दिया गया. इससे छोटे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल गई. बिजली का उपयोग करने वालों में सबसे बड़ी आबादी शहरी ही है. बिजली का उपयोग केवल लाइट, पंखा और कूलर के लिए करने वालों को इसका पूरा लाभ मिला. इससे बड़े उपभोक्ताओं को भी प्रथम 400 यूनिट पर बिजली बिल हाफ का लाभ मिलता रहा. रसोई गैस सिलिण्डरों की बढ़ती कीमतों ने इंडक्शन प्लेट और कुकर के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया.

रजिस्ट्री शुल्क में बड़ी राहत

पूर्ववर्ती डॉ रमन सिंह सरकार में जमीन का पंजीयन न केवल सरकार के राजस्व का एक बड़ा स्रोत बन गया था बल्कि इसमें लगाई गई तमाम शर्तें भी आम आदमी के लिए तकलीफदेह थीं. 15 साल के कार्यकाल में रमन सरकार ने जमीन रजिस्ट्री शुल्क में लगातार इजाफा किया. कांग्रेस की भूपेश नीत सरकार ने सत्ता संभालते ही रजिस्ट्री शुल्क में 30 प्रतिशत की छूट दे दी. यही नहीं पिछले पांच साल में रजिस्ट्री शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है. इसका लाभ भी शहरी क्षेत्र को ही ज्यादा मिला जहां मकान, दुकान की कीमतें आसमान छू रही हैं.

छोटे भूखण्डों की रजिस्ट्री शुरू

शहरी आबादी का सबसे बड़ा सपना अपना घर होता है. रमन सरकार ने पांच डिसमिल से छोटे भूखण्डों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी. इससे प्लाट खरीदना और उसपर अपने हिसाब से मकान बनवाना बेहद मुश्किल हो गया था. इसका सीधा लाभ रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ियों को मिला जिन्होंने अनाप-शनाप कीमतों पर फ्लैट और मकान बेचना शुरू कर दिया. भूपेश सरकार ने छोटे भूखण्डों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटा दिया. इससे जहां लोगों का अपने मकान का सपना पूरा हुआ वहीं छोटे ठेकेदारों को भी काम मिल गया.

पट्टे की जमीन का मालिकाना हक

विभिन्न सरकारों ने समय समय पर गरीबों को नजूल जमीन पर पट्टे दिये थे. पट्टे की जमीन पर लाखों लोग मकान बनाकर निवास करते रहें. पर इन मकानों को न तो बेचा जा सकता था और न ही उसकी रजिस्ट्री होती थी. भिलाई के हुडको का मामला भी इसी पेंच में फंसा हुआ था. इसलिए लोग औने-पौने दाम में अपना मकान बेचने के लिए मजबूर होते थे. क्रेता भी सशंकित रहता था. पट्टे की जमीन या मकान पर बैंक भी ऋण नहीं देते थे जिसके कारण सूदखोरों की चांदी थी. भूपेश सरकार ने निर्धारित शासकीय दर पर लगने वाले रजिस्ट्री शुल्क की मात्र 10 प्रतिशत राशि पर रजिस्ट्री कर पट्टे के हितग्राहियों को मालिकाना हक दिलाया.

कार्यालयीन भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट

विभिन्न प्रकार के सरकारी दस्तावेज हासिल करना आम आदमी के लिए हमेशा परेशानी का सबब रहा है. इसके लिए न केवल उसे सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटने पड़ते थे बल्कि बाबुओं की मुट्ठी भी गर्म करनी पड़ती थी. मुख्यमंत्री मितान योजना से इस परिपाटी पर विराम लगा दिया गया. अब आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, इत्यादि बनवाने शहरी जनता को सिर्फ हेल्पलाइन नं 14545 पर कॉल करना होता है. इसके बाद दस्तावेज को मुख्यमंत्री मितान उनके घर छोड़कर कर आता है. अब तक 96 हजार 268 से भी ज्यादा लोग इस सेवा का लाभ उठा चुके हैं. इससे कार्यालयीन भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी आई है.

इस योजना से दी कोरोना-काल को मात

कोरोना काल में लगाए गए लंबे लॉकडाउन से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों एवं छोटे व्यापारियों का जीवन संकट में आ गया था. शहरों में व्यापार करने वाले छोटे-छोटे दुकानदार, बर्बादी की कगार पर आ गए थे. भूपेश सरकार की योजनाओं ने परोक्ष रूप से स्थिति को संभाला. किसानों की कर्जमाफी, 2500 रुपए में धान खरीदी और बोनस, कृषि मजदूरों को 7000 रुपए सालाना देना प्रारंभ किया गया. लोगों ने शहरों में जाकर खरीदारी की. जिससे दुकानदारों का व्यापार भी समृद्ध हुआ. जबकि पूरे देश में मंदी की स्थिति रही.

दिल्ली वाले कबूल करेंगे दीपक बैज की चुनौतियां..?

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बस्तर सांसद दीपक बैज ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय रायपुर में भाजपा का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए दिल्ली से आने वाले भाजपा के शीर्ष नेताओं से बस्तर से लेकर सरगुजा तक खनिज और कोल खनन में अडानी को निशाने पर लेते हुए तीखे सवाल उठाए हैं और जवाब मांगे हैं, क्या भाजपा के दिग्गज नेता दीपक बैज की चुनौती स्वीकार करने तैयार हैं, यह बस्तर की धरती पर जिज्ञासा का विषय बन गया है. प्रदेश कांग्रेस के कमांडर बस्तर सांसद दीपक बैज ने भाजपा की राज्य सरकार के 15 साल के तमाम कथित घोटालों को उजागर करने के साथ ही उनसे संबंधित तत्कालीन मंत्रियों को भी नामजद किया है. कांग्रेस की ओर से उन्होंने भाजपा का काला चिट्ठा नाम के दस्तावेज में एक-एक घोटाले और घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया है. छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासनकाल में जो कुछ भी हुआ, वह छत्तीसगढ़ की जनता जानती है. इसीलिए 15 साल बाद भाजपा को ऐसा रुखसत किया गया कि बीते 5 साल में राज्य में वह कोई चुनाव नहीं जीत पाई. हालांकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय कारणों से छत्तीसगढ़ में भाजपा को उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली. भाजपा ने सोचा भी नहीं होगा कि 2018 के अंत में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पराजित होने के बाद वह लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीट जीत लेगी. उस समय निश्चित तौर पर पूरे देश में मोदी के नाम की आंधी चल रही थी लेकिन बस्तर में दीपक बैज ने जो कर दिखाया, वह अद्भुत है. बस्तर ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को चुना और लोकसभा चुनाव में बस्तर में दीपक बैज कांग्रेस की रोशनी बनकर उभरे. उन्होंने विधायक रहते हुए भी बस्तर के मुद्दों पर काफी काम किया और सांसद बनने के बाद तो वह बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की आवाज बन गए. उन्हें सक्रियता और आक्रामकता के साथ केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का यह प्रतिफल मिला कि उन्हें कांग्रेस ने चुनाव के ठीक पहले प्रदेश संगठन की बागडोर सौंप दी. दीपक बैज के तेवर भाजपा के खिलाफ अब पहले से अधिक तीखे हैं. वह राज्य के भाजपा नेताओं से ज्यादा केंद्र के भाजपा नेताओं के लिए चुनौती बनकर सामने आए हैं. कदाचित उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम और काम के सामने जरा सा भी टिक पाए. रही बात केंद्र के भाजपा नेताओं की तो दीपक बैज दिल्ली में भी इन्हें चुनौती देते रहते हैं फिर छत्तीसगढ़ में तो उनका खास स्वागत जरूरी है.

कांग्रेस की तरकश में कई तीर

वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस धारदार अंदाज में और ठोस मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है, लेकिन बस्तर संभाग के मतदाताओं को साधने के लिए कांग्रेस के पास मुद्दों की भरमार है. नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के अलावा नंदराज पहाड़, आरक्षण, स्थानीय बेरोजगारों को नौकरियों में प्राथमिकता कांग्रेस के लिए भाजपा के खिलाफ चुनावी युद्ध में रामबाण सिद्ध हो सकते हैं.

» हेमंत कश्यप, जगदलपुर

भूपेश बघेल सरकार की जनहितकारी योजनाओं को लेकर तो कांग्रेस राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों में जाएगी, इस बात में कोई शक नहीं है. अपनी पहली पारी में ही कांग्रेस सरकार ने उच्च दर पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोबर एवं गोमूत्र खरीदी, गोठान योजना, बेरोजगारी भत्ता, रीपा योजना आदि के माध्यम से समाज के हर वर्ग का दिल जीत लिया है. छत्तीसगढ़ के किसान कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हैं और कांग्रेस के प्रति मेहरबान नजर आ रहे हैं. पुनः सरकार बनने पर कांग्रेस ने धान की खरीदी 2650 रु. प्रति क्विंटल की दर से करने की घोषणा कर और खरीदी लिमिट को 20 क्विंटल प्रति एकड़ करके किसानों को अपने पाले में कर लिया है. छत्तीसगढ़ में कृषक परिवारों की अधिकता है और मजदूर वर्ग भी कृषि आधारित रोजगार पर ही ज्यादा निर्भर हैं. सालाना 7 हजार रु. का मान धन देकर भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ भी भूपेश बघेल सरकार ने न्याय किया है. इस तरह अभी से साफ हो गया है कि एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है. ये सारे कारक तो बस्तर में कांग्रेस के पक्ष में प्रभावी हैं ही, इनके अलावा कांग्रेस की

तरकश में भाजपा के खिलाफ कई और रामबाण भी हैं. इस ब्रम्हास्त्र और रामबाण के माध्यम से भाजपा को कांग्रेस 'बारहों खाने' चित्त कर सकती है. आशय यह कि बस्तर संभाग की सभी बारह विधानसभा सीटों पर कांग्रेस शानदार जीत दर्ज करा सकती है.

क्या है नंदराज पहाड़ का मसला?

नंदराज पहाड़ वो मसला है, जिसे लेकर बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद दीपक बैज लंबे अरसे से संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ते आ रहे हैं.लौह अयस्क के अकूत भंडार से समृद्ध बैलाडीला पर्वत श्रृंखला के नंदराज पहाड़ का गर्भ भी कच्चे लोहे से भरा हुआ है. इस पहाड़ के बड़े भाग को लौह अयस्क खनन और इस अयस्क के उपयोग के लिए अडानी समूह को लीज पर दे दिया गया है. नंदराज पहाड़ की तलहटी में बसे गांवों के ग्रामीणों के पुरजोर विरोध और ग्रामसभाओं द्वारा पारित विरोध प्रस्ताव के बावजूद डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में यह कदम उठाया गया था. सांसद दीपक बैज इस फैसले का विरोध कई बार लोकसभा में कर चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद दीपक बैज इस मुद्दे को संसद के बाद सड़क पर भी ले आए. बताते हैं कि दर्जनों गांवों के ग्रामीण नंदराज पहाड़ को लीज पर दिए जाने से नाखुश हैं और विधानसभा चुनाव में लोगों की यह नाराजगी भाजपा को भारी पड़ने वाली है, कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा जरूर बनाएगी.

नगरनार पर करार : लोग बेकरार

एनएमडीसी द्वारा जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नगरनार में स्थापित इस्पात संयंत्र को कथित तौर पर बेचने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र से किए जा रहे करार के खिलाफ भी बस्तर संभाग के ग्रामीण बेकरार नजर आ रहे हैं. जन चर्चा है कि मोदी सरकार इस स्टील प्लांट को एक बड़े औद्योगिक घराने के हवाले करने का फैसला कर चुकी है. केंद्र सरकार का यह कदम भी भाजपा पर भारी पड़ता नजर आ रहा है. नगरनार समेत एक दर्जन से भी अधिक गांवों के ग्रामीणों की कृषि और पड़त भूमि अधिग्रहित की गई है. अधिग्रहण के दौरान कहा गया था कि नगरनार इस्पात संयंत्र में हर प्रभावित परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी. सामुदायिक विकास योजना के तहत संयंत्र के परिधीय गांवों के विकास के कार्य कराए जाएंगे, अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी, नगरनार में उत्कृष्ट स्कूल और सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की स्थापना की जाएगी. मगर दुख की बात है कि अधिकांश दावे थोथे ही साबित हुए हैं. कई प्रभावित परिवारों को संयंत्र में नौकरी मिली और कई अभी भी नौकरी मिलने की आस लगाए बैठे हैं, आयु सीमा को पार करते जा रहे हैं. कुछ दिन पहले तक एक प्रभावित परिवार की दो बेटियां नौकरी की मांग करते हुए संयंत्र के बाहर धरने पर बैठ गईं थीं. संयंत्र में ट्रांसपोर्टिंग का काम भी बाहरी लोगों को दे दिया गया है. स्थानीय ग्रामीण ट्रांसपोर्टर और बस्तर परिवहन संघ के सदस्य ट्रांसपोर्टिंग का काम स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को देने की मांग को लेकर लंबे समय तक धरना दे चुके हैं. वहीं सर्व आदिवासी समाज और पिछड़ा वर्ग समाज भी नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण के विरोध में तथा संयंत्र में स्थानीय बेरोजगारों और मजदूरों को नौकरी देने की मांग को लेकर मोर्चा खोल चुका है.

जायज है सांसद बैज की चिंता

सांसद दीपक बैज और जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण के खिलाफ शुरू से मुखर रहे हैं. सांसद दीपक बैज जहां संसद में निजीकरण के विरोध में लगातार आवाज उठाते आए हैं, वहीं विधायक एवं संसदीय सचिव इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं. बस्तर के ये दोनों ही जागरूक जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार के फैसले के विरुद्ध मोर्चा सम्हाले हुए हैं. सांसद दीपक बैज की चिंता यह रही है कि निजीकरण के बाद नगरनार इस्पात संयंत्र में आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और गरीब तबके के योग्य युवाओं को आरक्षण के आधार पर नौकरियों में भागीदारी नहीं मिल पाएगी. श्री बैज अपनी यह चिंता लोकसभा में भी व्यक्त कर चुके हैं. एक दफे उन्होंने संसद में कहा था कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की बाध्यता नहीं है, ऐसे में नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण हो जाने पर आरक्षित वर्गों को पर्याप्त नौकरियां नहीं मिल पाएंगी. श्री बैज की यह चिंता बिल्कुल जायज है, यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद दीपक बैज और बस्तर जिले के प्रभारी एवं छग शासन के उद्योग मंत्री कवासी लखमा की पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार नगरनार इस्पात संयंत्र को खुद चलाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज चुकी है. भूपेश बघेल की मंशा है की संयंत्र को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के अधीन कर दिया जाए या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के हवाले कर दिया जाए.

आरक्षण का लंबित प्रकरण

भूपेश बघेल सरकार अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीबों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध रही है. भूपेश बघेल केबिनेट ने इन सभी वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करते हुए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राजयपाल के पास भेज दिया है. कई माह बीत जाने के बाद भी इस प्रस्ताव को राजभवन से मंजूरी नहीं मिल पाई है. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार के दबाव में इस मसले को लटकाकर रखा गया है. कांग्रेस इसे पहले ही बड़ा मुद्दा बना चुकी है. यह मुद्दा बस्तर जैसे अनुसूचित जनजाति बहुल संभाग में भाजपा का गणित बिगाड़ सकता है. इस तरह देखा जाए तो बस्तर संभाग के लिए कांग्रेस के पास एक से बढ़कर एक ब्रम्हास्त्र, रामबाण और मिसाइलें हैं, जो भाजपा की चुलें हिलाने में सक्षम हैं.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथित दोस्त गौतम अडाणी पर हुई हर चोट पर भाजपा तिलमिला जाती है. भाजपा शासन के 15 सालों में छत्तीसगढ़ अडाणी की कंपनियों के लिए चारागाह बना हुआ था. पर भूपेश बघेल की सरकार आते ही उसका खेल यहां से खत्म होने लगा. पहले उसके हाथ से बस्तर की खदान गई और फिर हसदेव वनक्षेत्र में आदिवासियों के विरोध के बाद वहां की खदानों को भी बंद करना पड़ा. इससे भाजपा तिलमिलाई हुई है और किसी भी कीमत पर छत्तीसगढ़ की सत्ता में लौटना या उसमें भागीदार बनना चाहती है.

भाजपा की कमजोर नब्ज अडाणी

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023

» मुख्यमंत्री बनते ही नंदराज पहाड़ का लीज निरस्त

» हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ काटने पर लगाई रोक

» जीत नहीं तो न सही, भागीदारी चाहेगी भाजपा

» लेमरू एलीफेंट कॉरीडोर के लिए आरक्षित

लखन लाल

भूपेश बघेल Vs गौतम अडाणी

- केन्द्र सरकार के करीबी गौतम अडाणी के पास छत्तीसगढ़ मे सर्वाधिक खदानें थीं. भाजपा की रमन सरकार ने अडाणी की कंपनी को छत्तीसगढ़ में आठ खदानें आबंटित कर दी थीं. इस मामले में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएमडीसी) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की उपेक्षा की गई. भूपेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़कर भैंसाकन्हार सहित कुछ खदानों को बचा लिया.

- इसी बीच बस्तर के नंदराज पहाड़ का मामला उछला. यहां आयरन ओर के उत्खनन के लिए भी अडाणी को पट्टा जारी किया जा चुका था. इस पहाड़ को आदिवासी समाज अपने ईष्ट देव का निवास स्थान मानते हैं. वे प्राण देकर भी इसकी रक्षा के लिए डट गए. चूंकि लीज जारी हो चुकी थी मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को लीज प्रक्रिया के अध्ययन के काम पर लगा दिया. पता चला कि लीज के इस प्रस्ताव का अनुमोदन केवल पंचायत ने किया था. जनसुनवाई नहीं की गई थी. इसी एक कमी के चलते भूपेश सरकार ने लीज निरस्त करने हेतु केंद्र सरकार को पत्र लिखा जिसे केन्द्र को मानना पड़ा. यह अडाणी पर भूपेश बघेल द्वारा पहली चोट थी.

- हसदेवअरण्य क्षेत्र का मामला भी ऐसा ही था. यहां कोयला उत्खनन का ठेका भी अडाणी की कंपनी को दिया गया था. इस लीज में तमाम नियम कायदों को ताक पर रखते हुए कंपनी ने यहां के जंगलों को भारी नुकसान पहुंचाया. इस अरण्यक्षेत्र को मध्यभारत का फेफड़ा भी कहा जाता है. आदिवासियों ने इन जंगलों को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया. सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल चलकर राजभवन तक पहुंचे. भूपेश सरकार इन जंगलों को बचाने में सफल हुई.

- इसी तरह कोरबा के हसदेव अभ्यारण्य में केंद्र सरकार द्वारा 40 कोयला खदानों को नीलामी करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया था, जिसे भूपेश बघेल सरकार ने लेमरू एलिफेंट कारीडोर घोषित कर सुरक्षित कर दिया, क्योंकि ये हाथियों का विचरण स्थान था. पूर्व में की गई कोयला खदान की उत्खनन से हाथी गांवों एवं शहरों की ओर आने लगे जिससे जन-धन की काफी क्षति हुई. चुनावी हानि को देखते हुए केन्द्र सरकार को उक्त खदानों की नीलामी से रोक लगाने मजबूर होना पड़ा. ये भी भूपेश सरकार और छत्तीसगढ़ की जनता की बड़ी जीत है.

छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है. यहां रहने वालों को अमीर धरती के गरीब लोग भी कहा जाता है. 1 नवम्बर सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य तो बन गया पर जिन उद्देश्यों के साथ इस छोटे से राज्य का निर्माण किया गया था, उस पर कभी काम नहीं हुआ. 2018 में चुनाव जीतकर सत्ता में आई भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्माताओं का सपना पूरा करने के लिए जोरदार पहल प्रारंभ की. भूपेश स्वयं चाहते थे कि राज्य के खनिज का अंधाधुंध दोहन पर रोक लगाई जाए तथा छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य सुरक्षित रखा जाए. इसके साथ ही यहां के पारिस्थितिक तंत्र को भी सुरक्षित रखते हुए विकास किया जाए.

विकास के भूपेश बघेल मॉडल को न केवल पूरे देश में बल्कि अमेरिका में जा बसे छत्तीसगढ़ वासियों का भी खुला समर्थन मिला. आज पूरी दुनिया खदानों और खनिज आधारित उद्योगों का विकल्प तलाश रही है. भूपेश का मॉडल था कृषि आधारित उद्योग एवं मिट्टी और भूजल का संरक्षण व पुनर्भरण. नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी योजना के साथ भूपेश ने इसका आगाज सत्ता में आते ही कर दिया था. स्वयं केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं के लिए भूपेश सरकार की पीठ थपथपायी और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले.

भूपेश बघेल ने सरकार बनते ही अपने इरादे साफ कर दिये थे. नई उद्योग नीति के लिए बुलाई गई उद्योगपतियों की बैठक में ही उन्होंने साफ कर दिया था कि खनिज आधारित उद्योग न तो राज्य हित में हैं, न पर्यावरण हित में और न ही इससे पर्याप्त रोजगार पैदा हो सकते हैं. इसके बजाय उन्होंने कृषि और वनोपज आधारित उद्योगों का प्रस्ताव दिया. साथ ही यह भरोसा भी दिया कि एग्रो इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी सहायता देगी. उद्योगजगत ने इसका स्वागत किया. पिछले पांच सालों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के मामले में छत्तीसगढ़ ने संतोषजनक प्रगति की है.

अब भाजपा यह समझ चुकी है कि भूपेश बघेल की सरकार के रहते छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लुटाया नहीं जा सकता. समझा जाता है कि इन्हीं खदानों की कमाई से पार्टी की फंडिंग होती है. इसलिए वह किसी भी तरह छत्तीसगढ़ की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है. पर फिलहाल उसे संभव नहीं लगता. इसलिए नई रणनीति के तहत भाजपा तमाम साम-दाम-दंड-भेद के द्वारा कम से कम 35 सीटें जीतना चाहती है. अगर यह संभव हुआ तो वह चुनाव के बाद कांग्रेस तथा अन्य छोटे दलों के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी. ईडी के छापों से उसने इसकी जमीन पहले ही तैयार कर रखी है. जिस तरह असम के मुख्यमंत्री हिमन्ता बिस्वा सरमा को भाजपा ने अपनी ओर मिलाया और उनके खिलाफ सारे आरोप समाप्त कर दिये, उसी तरह ईडी जांच में फंसे लोगों को ऑफर देने की सूरत बन जाएगी. यदि कांग्रेस की सरकार बनाना मजबूरी भी हुई तो वे अपने पिट्ठू को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहेंगे.

आत्मनिर्भर बना रहे हैं भूपेश

भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन से जुड़े रहे हैं. किसानों को उनका हक दिलाने और बीएसपी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानीय युवाओं की भर्ती को लेकर वे जेल भी जा चुके हैं. उल्लेखनीय है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नद्रष्टा डॉ. खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य की मांग उठायी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि छत्तीसगढ़ राज्य सिर्फ नक्शे में नहीं चाहिए. ऐसा छत्तीसगढ़ चाहिए, जिसमें स्थानीय निवासी आर्थिक रूप से सक्षम हों तथा छत्तीसगढ़ की संस्कृति समृद्ध हो. उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर, महिला तथा युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने का ईमानदारी से प्रयास किया. साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का भी काम किया.

नए चेहरों पर भरोसा नहीं कर पाई पार्टी

महिला आरक्षण की भी नहीं दिखी झलक

चयन समिति पर ही उठने लगे सवाल

भाजपा को बासी-कढ़ी में उबाल की उम्मीद

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

लगभग तीन महीने की भारी भरकम कवायद के बाद भाजपा ने चुनाव अधिसूचना के पहले-पहले अपने 85 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी. पार्टी ने अधिकांश सीटों पर पुराने चेहरों को ही फिर से मौका दिया है. इनमें से कई तो सालों से अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. चुनावों से ऐन पहले महिला आरक्षण बिल पास कर सुर्खियों में आई भाजपा ने महिला प्रत्याशियों पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया है. पार्टी ने केवल 13 महिलाओं को ही उम्मीदवार बनाया है जबकि छत्तीसगढ़ की मौजूदा विधानसभा में 18 फीसदी अर्थात 16 महिला सदस्य हैं.

भाजपा ने पहली सूची में 21 तथा दूसरी सूची में 64 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी. 90 सदस्यीय विधानसभा की शेष 5 सीटों पर पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं. ये सीटें हैं पंढरिया, बेमेतरा, कसडोर, बेलतरा और अंबिकापुर. भाजपा ने अपने सभी विधायकों को फिर से मैदान में उतारा है. पार्टी ने रमन सिंह की सरकार में मंत्री रहे 17 नेताओं को भी टिकट दिया है. इनमें से ज्यादातर 2018 का चुनाव हार गए थे.

बस्तर क्षेत्र की बात करें तो भाजपा ने 12 में से 4 सीटों पर उन चेहरों पर ही दांव लगाया है जिनको 2018 के चुनाव में शिकस्त झेलनी पड़ी थी. इनमें तीन पूर्व मंत्रियों केदार कश्यप, लता उसेंडी और महेश गागड़ा के नाम शामिल हैं. पार्टी ने 43 युवा उम्मीदवारों पर दांव लगाया है तो अब तक घोषित उम्मीदवारों में इतने ही नए चेहरे भी हैं.

उम्मीदवारों की इस सूची में 11 विधायकों के नाम हैं तो 13 ऐसे नेताओं के भी जो चुनाव हार चुके हैं. इसे लेकर पार्टी के भीतर और कार्यकर्ताओं के बीच भी सवाल उठ रहे हैं. कहा जा रहा है कि भाजपा के नेता और प्रदेश नेतृत्व, लोकसभा चुनाव के बाद शिथिल रहे. इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी कई जगहों पर नया नेतृत्व तैयार नहीं कर सकी. ऐसे में मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा को कई इलाकों मे न चाहते हुए भी हारे हुए नेताओं पर ही दांव लगानी पड़ी. इनसे बेहतर विकल्प पार्टी नहीं तलाश कर पाई.

भाजपा के स्टार प्रत्याशी

भाजपा प्रत्याशियों में दो आईएएस, दो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा एक पूर्व मुख्यमंत्री सहित 12 पूर्व मंत्री शामिल हैं. इनमें से 10 के पास कानून की डिग्री है. वकालत की डिग्री रखने वालों में ननकीराम कंवर, बृजमोहन अग्रवाल, पुरन्दर मिश्रा, अरुण साव, धरमलाल कौशिक, किरणदेव, संतोष लहरे, टंकराम के पास भी कानून की डिग्री है जबकि कृष्णकांत कानून के विद्यार्थी हैं. प्रत्याशियों में 4 डाक्टर भी हैं जिनमें से दो एमबीबीएस, एमएस और एमडी हैं. इनमें डॉ कृष्णमूर्ति बांधी, दिनेशलाल, खिलावन साहू एवं स्वयं डॉ रमन सिंह शामिल हैं. सबसे कम पढ़े लिखे प्रत्याशी साजा से ईश्वर साहू हैं जो केवल 5वीं तक ही औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर पाए हैं. एक प्रत्याशी अनुज शर्मा पद्मश्री हैं.

इन सीटों पर महिला प्रत्याशी

महिला प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा ने पहली सूची में भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े, प्रतापपुर से शकुंतला सिंह पोर्ते, सरायपाली से सरला कोसरिया, खल्लारी से अलका चंद्राकर, खुज्जी से गीता घासी साहू, कांकेर से आशाराम नेताम के नाम तय कर दिये गये थे. दूसरी सूची में भरतपुर सोनहत से सांसद रेणुका सिंह, सामरी से उधेश्वरी पैकरा, पत्थलगांव से सांसद गोमती साय, लैलूंगा से सुनीति सत्यानंद राठिया, सारंगढ़ से शिवकुमारी चौहान, चंद्रपुर से बहू रानी संयोगिता सिंह जूदेव, धमतरी से रंजना दीपेन्द्र साहू को मौका दिया गया है.

इस स्थिति के लिए भाजपा खुद जिम्मेदार

15 साल तक सत्ता सुख भोगने के बाद भाजपा सत्ता से क्या गई लगभग पूरी पार्टी ही ठंडे बस्ते में चली गई. पार्टी के अधिकांश कद्दावर नेता एसी कमरों में ही आराम फरमाते रह गए. पिछले चुनाव से पहले ही कार्यकर्ताओं ने बता दिया था कि पार्टी की इस बार चुनाव में दुर्गति होने वाली है. उन्होंने इसका कारण मुख्यमंत्री को घेरे हुए कॉकस, सीएम के परिवार का बढ़ता हस्तक्षेप संगठन को सत्ता से बहुत दूर लेकर जा चुका था. संगठन और सत्ता के बीच कोई तालमेल ही न रह गया था. इसकी रिपोर्ट आलाकमान को भी थी. संगठन की बात सच साबित हुई. इसके बावजूद हाईकमान ने ज्यादा कुछ नहीं किया.

स्थिति इस बार भी ज्यादा नहीं बदली

कार्यकर्ता संसाधन के नहीं बल्कि सम्मान के भूखे होते हैं जो उन्हें पिछली सरकार में नहीं मिला था. उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक बार करारी शिकस्त खाने के बाद पार्टी आलाकमान को अक्ल आ गई होगी. उन्होंने लगा था कि इस बार संगठन की पूछपरख बढ़ेगी तथा टिकट वितरण में भी उनकी चलेगी. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. हालांकि पार्टी ने जमीनी हकीकत पता करने और कार्यकर्ताओं के मन को टटोलने के लिए एजेंसी भी हायर की किन्तु इसका कोई खास असर जमीन पर नहीं दिखा. कार्यकर्ता एक बार फिर हाशिए पर चले गए और टिकट वितरण में पिटे हुए नेताओं की ही चल गई.

क्या था सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट में

सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट जिसने तलब की थी उसे मिल गई. इसमें किसके बारे में क्या कहा गया था, किससे एजेंसी ने बात की, इसे लेकर अटकलों का ही दौर चलता रहा. केन्द्रीय चुनाव समिति ने जिस सर्वेटीम को नियुक्त किया था, उसे राज्य में पार्टी के बड़े नेताओं ने हाईजैक कर लिया. उन्होंने अपनी पसंद के नामों को सर्वे टीम की प्रस्तावित सूची में शामिल करवा दिया. यही सूची बाद में केन्द्रीय चुनाव समिति को सौंपी गई. केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं शामिल थे.

केवल जीतने वालों को मिलेगा टिकट - माथुर

चुनाव समिति में प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री ओम माथुर, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, सह प्रभारी नवीन नितिन, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, सह प्रभारी छत्तीसगढ़ शिव प्रकाश तथा केन्द्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल थे. बताते हैं सूची देखकर ओम माथुर, बीएल संतोष, नवीन नितिन, शिव प्रकाश जैसे लोग बैठक से उठकर चले गए थे. ओम माथुर इस बात से भी नाराज थे कि सूची लीक हो गई. उन्होंने ने अगस्त में ही कह दिया था कि इस बार पार्टी केवल जिताऊ प्रत्याशियों को ही टिकट देगी. ऐसे सीनियर कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलेगा जिनके जीतने की संभावना कम हो.

विधानसभा चुनाव 2023 : विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की सूची

विधानसभा क्षेत्र	भाजपा प्रत्याशी	कांग्रेस प्रत्याशी	जनता कांग्रेस प्रत्याशी	जोहार छत्तीसगढ़	आम आदमी पार्टी
(01) भरतपुर सोनहत	रेणुका सिंह	गुलाब सिंह कमरो	सुखमंति सिंह	--	सुखवंती सिंह
(02) मनेन्द्रगढ़	श्याम बिहारी जयसवाल	रमेश सिंह	आदित्य राज डेविड	--	मनसुर मेमन
(03) बैकुंठपुर	भैयालाल राजवाड़े	अंबिका सिंह देव	दुर्गेश साहू	--	आकाश जायसवाल
(04) प्रेमनगर	भूलन सिंह मरावी	खेलसाय सिंह	जगलाल सिंह	--	मालती रजवाड़े
(05) भटगांव	लक्ष्मी राजवाड़े	पारसनाथ राजवाड़े	समय लाल पाटिल	--	सुरेंद्र गुप्ता
(06) प्रतापपुर (अजजा)	शकुंतला सिंह पोर्थे	राजकुमारी मरावी	सुंदरलाल श्याम	--	राजा राम श्याम
(07) रामानुजगंज (ST)	रामविचार नेताम	डॉ. अजय तिर्की	ज्ञानी सिंह	--	नीलम ठाकुर
(08) सामरी (अजजा)	उधेश्वरी पैकरा	विजय पैकरा	प्रभाबेला मरकाम	--	देव गणेश टेकाम
(09) लुण्ड्रा (अजजा)	प्रबोध मिंज	डॉ. प्रीतमराम	इटाउर तिर्की	--	एलेक्जेंडर
(10) अंबिकापुर	राजेश अग्रवाल	टी.एस.सिंहदेव	हकीम अब्दुल माजिद	--	--
(11) सीतापुर (अजजा)	राम कुमार टोप्पो	अमरजीत भगत	जेम्स टोप्पो	--	मुन्ना टोप्पो
(12) जशपुर (अजजा)	रायमुनि भगत	विनय कुमार भगत	सरहुल भगत	--	प्रकाश टोप्पो
(13) कुनकुरी (अजजा)	विष्णु देव साय	यूडी मिंज	चाल्स इक्का	--	लेओस मिंज

विधानसभा क्षेत्र	भाजपा प्रत्याशी	कांग्रेस प्रत्याशी	जनता कांग्रेस प्रत्याशी	जोहार छत्तीसगढ़	आम आदमी पार्टी
(14) पत्थलगांव (अजजा)	गोमती साय	रामपुकार सिंह	नेहरू लकड़ा	--	राजा राम लकड़ा
(15) लैलूंगा (अजजा)	सुनीति सत्यानंद राठिया	विद्यावती सिदार	मनीषा गोंड़	--	कुंति सिदार
(16) रायगढ़	ओ.पी. चौधरी	शक्राजीत नायक	मधुबाई किन्नर	सुनील मिंज	गोपाल बपुड़िया
(17) सारंगढ़ (अजा)	शिवकुमारी चौहान	उत्तरी जांगड़े	डॉ. छबिलाल राठे	--	देव प्रसाद कोशले
(18) खरसिया	महेश साहू	उमेश पटेल	परिमल यादव	यशवंत निषाद	विजय जायसवाल
(19) धरमजयगढ़	हरिश्चंद्र राठिया	लालजीत राठिया	जोगेन्द्र इक्का	--	--
(20) रामपुर (अजजा)	ननकीराम कंवर	फूलसिंह राठिया	बालमुकुंद राठिया	--	--
(21) कोरबा	लखनलाल देवांगन	जयसिंह अग्रवाल	रज्जाक अली	--	विशाल केलकर
(22) कटघोरा	प्रेमचन्द्र पटेल	पुरुषोत्तम कंवर	संपूरण दास कुलदीप	सुरेन्द्र प्रसाद राठौर	चंद्रकांत डिक्सेना
(23) पाली-तानाखार	रामदयाल उईके	दुलेश्वरी सिदार	छत्रपाल सिंह कंवर	शिवरात सिंह पैंकरा	सोबराम सिंह सैमा
(24) मरवाही (अजजा)	प्रणव कुमार मरपच्ची	डॉ. केके ध्रुव	--	--	भावेश वरकड़े
(25) कोटा	प्रबल प्रताप सिंह जूदेव	अटल श्रीवास्तव	डॉ. रेणु जोगी	--	पंकज जेम्स
(26) लोरमी	अरूण साव	थानेश्वर साहू	सागर सिंह बैस	परस राम यादव	मनभजन टंडन
(27) मुंगेली (अजा)	पुन्नूलाल मोहले	संजीत बैनर्जी	डॉ. सरिता भारद्वाज	नोबिल नवरंग	दीपक पाले
(28) तखतपुर	धरमजीत सिंह	डॉ. रश्मि आशीष सिंह	दिनेश कौशिक	जयचंद कश्यप	--
(29) बिल्हा	धरमलाल कौशिक	सियाराम कौशिक	नेहा भारती	संतोष साहू	जसबीर सिंह
(30) बिलासपुर	अमर अग्रवाल	शैलेश पांडे	अखिलेश पांडेय	--	डॉ. उज्ज्वला कराड़े
(31) बेलतरा	सुशांत शुक्ला	विजय केशरवानी	--	--	राकेश यादव
(32) मस्तुरी (अजा)	डॉ. कृष्णमूर्ति बंदी	दिलीप लहरिया	चांदनी भारद्वाज	बॉबी पाले	धरम दास भार्गव
(33) अकलतरा	सौरभ सिंह	राघवेंद्र सिंह	डॉ. ऋचा जोगी	--	आनंद प्रकाश मिरी
(34) जांजगीर-चांपा	नारायण चंदेल	व्यास कश्यप	रविन्द्र द्विवेदी	बीना साहू	परमेश्वर प्रसाद
(35) सक्ती	डॉ. खिलावन साहू	डॉ. चरणदास महंत	राजकुमार पटेल	तूफान सिंह चंदेल	अनुभव तिवारी
(36) चंद्रपुर	संयोगिता सिंह जूदेव	रामकुमार यादव	गणेश चालक	सतीश पांडेय	--
(37) जैजैपुर	कृष्णकांत चंद्र	बालेश्वर साहू	टेकचंद चन्द्रा	रामपाल कश्यप	दुर्गालाल केंवट
(38) पामगढ़ (अजा)	संतोष लहरे	शेषराज हरबंस	गोरेलाल बर्मन	--	श्यामलाल बंजारे
(39) सरायपाली (अजा)	सरला कोसरिया	चातुरी नंद	किस्मतलाल नंद	--	--
(40) बसना	संपत अग्रवाल	देवेंद्र बहादुर सिंह	डॉ. अनामिका पाल	--	--
(41) खल्लारी	अलका चंद्राकर	द्वारिकाधीश यादव	रेखराम बाघ	गैंदलाल डडसेना	नीलम ध्रुव
(42) महासमुंद	योगेश्वर राजू सिन्हा	डॉ. रश्मि चंद्राकर	राशि महिलांग	--	संजय यादव
(43) बिलाईगढ़ (अजा)	डॉ. दिनेशलाल जागड़े	कविता प्राण लहरे	प्रो. ब्रम्हानंद मारकंडे	रामेश्वर सोनवानी	--
(44) कसडोल	धनीराम धीवर	संदीप साहू	बाबा मनहरण गुरूसाई	डी. देवेश वर्मा	लेखराम साहू
(45) बलौदा बाजार	टंकराम वर्मा	शैलेष त्रिवेदी	योगेश साहू	--	संतोष यदु
(46) भाटापारा	शिवरतन शर्मा	इंदर कुमार साव	जितेन्द्र बंजारे	चन्द्रकांत यदु	दादूराम प्रेमी
(47) धरसीवां	अनुज शर्मा	छाया वर्मा	डॉ. अमीन खान	अमित बघेल	--
(48) रायपुर ग्रामीण	मोतीलाल साहू	पंकज शर्मा	मनोज बंजारे	धीरेन्द्र साहू	तरूण वैद्य
(49) रायपुर पश्चिम	राजेश मूणत	विकास उपाध्याय	भगत हरबंश	ऋचा वर्मा	नंदन सिंह
(50) रायपुर उत्तर	पुरन्दर मिश्र	कुलदीप जुनेजा	मंशु निहाल	लक्ष्मी नाग	विजय गुरूबक्सनी
(51) रायपुर दक्षिण	बृजमोहन अग्रवाल	महंत राम सुंदर दास	प्रदीप साहू	मनीष ठाकुर	विजय झा

विधानसभा क्षेत्र	भाजपा प्रत्याशी	कांग्रेस प्रत्याशी	जनता कांग्रेस प्रत्याशी	जोहार छत्तीसगढ़	आम आदमी पार्टी
(52) आरंग (अजा)	गुरू खुशवंत सिंह	डॉ. शिवकुमार डहरिया	डॉ. के.आर. सोनवानी	--	परमानंद जंघेल
(53) अभनपुर	इंद्रकुमार साहू	धनेंद्र साहू	माखन ताम्रकार	यश साहू	--
(54) राजिम	रोहित साहू	अमितेश शुक्ला	भुनेश्वर निषाद	--	तेजराम विद्रोही
(55) बिंद्रानवागढ़	गोवर्धन राम मांझी	जनकलाल ध्रुव	टीकम नागवंशी	--	भागीरथी मांझी
(56) सिहावा (अजजा)	श्रवण मरकाम	अंबिका मरकाम	कांशीराम गोंड़	--	--
(57) कुरूद	अजय चंद्राकर	तारिणी चंद्राकर	तेजेश्वर कुर्रे	बसंत साहू	--
(58) धमतरी	रंजना दीपेंद्र साहू	ओमकार साहू	फिरोज खान	निखलेश साहू	--
(59) संजारी बालोद	राकेश यादव	संगीता सिंह	शकुंतला देवांगन	चन्द्रभान साहू	छविन्द्र साहू
(60) डौंडी लोहारा	देवलाल हलवा ठाकुर	अनिला भेड़िया	गिरवर सिंह ठाकुर	--	--
(61) गुंडरदेही	वीरेंद्र कुमार साहू	कुंवर सिंह निषाद	राजेन्द्र कुमार साय	डॉ. संदीप बेलचंदन	जसवंत सिन्हा
(62) पाटन	विजय बघेल	भूपेश बघेल	शीतकरण महिलवार	मधुकांत साहू	अमित हिरमानी
(63) दुर्ग ग्रामीण	ललित चंद्राकर	ताम्रध्वज साहू	ढालेश साहू	कामेश साहू	संजीत विश्वकर्मा
(64) दुर्ग शहर	गजेंद्र यादव	अरुण वोरा	संजय दुबे	पंकज चतुर्वेदी	--
(65) भिलाई नगर	प्रेम प्रकाश पांडे	देवेंद्र यादव	जहीर खान	ऋतुराज वर्मा	--
(66) वैशाली नगर	रिकेश सेन	मुकेश चंद्राकर	डॉ. दिवाकर भारती	योगेश साहू	--
(67) अहिवारा (अजा)	डोमन लाल कोरसेवाड़ा	निर्मल कोसरे	रीति देशलहरा	अरूण गंधर्व	--
(68) साजा	ईश्वर साहू	रविंद्र चौबे	डोमन देशलहरा	राजेन्द्र पटेल	वीर वर्मा
(69) बेमेतरा	दीपेश साहू	आशीष कुमार छाबड़ा	बहल सिंह वर्मा	--	प्रमोद साहू
(70) नवागढ़ (अजा)	दयाल बघेल	गुरू रूद्र कुमार	शेष नारायण कुर्रे	जितेन्द्र देशलहरा	
(71) पंडरिया	भावना बोहरा	नीलकंठ चंद्रवंशी	रवि चंद्रवंशी	--	चमेली कुर्रे
(72) कवर्धा	विजय शर्मा	मो. अकबर	सुनील केसरवानी	--	खड़गराज सिंह
(73) खैरागढ़	विक्रांत सिंह	यशोदा वर्मा	लक्की कुंवर नेताम	--	--
(74) डोंगरगढ़ (अजा)	विनोद खांडेकर	हर्षिता स्वामी बघेल	लोकनाथ भारती	--	--
(75) राजनांदगांव	डॉ. रमन सिंह	गिरीश देवांगन	शमशुल आलम	मनीष देवांगन	--
(76) डोंगरगांव	भरत लाल वर्मा	दलेश्वर साहू	मुकेश साहू	--	--
(77) खुज्जी	गीता घासी साहू	भोलाराम साहू	विनोद पुराम	--	--
(78) मोहला-मानपुर	संजीव साहा	इंद्रशाह मंडावी	नागेश पुराम	--	--
(79) अंतागढ़ (अजजा)	विक्रम उसेंडी	रूप सिंह पोटाई	--	--	संत राम सलाम
(80) भानुप्रतापपुर	गौतम उइके	सावित्री मंडावी	--	--	कोमल हुपेंडी
(81) कांकेर (अजजा)	आशाराम नेताम	शंकर ध्रुव	--	--	--
(82) केशकाल (अजजा)	नीलकंठ टेकाम	संतराम नेताम	--	--	जुगलकिशोर बोध
(83) कोंडागांव (अजजा)	लता उसेंडी	मोहन लाल मरकाम	शंकर नेताम	--	--
(84) नारायणपुर (अजजा)	केदार कश्यप	चंदन कश्यप	बलिराम कचलाम	--	नरेंद्र कुमार नाग
(85) बस्तर (अजजा)	श्री मनीराम कश्यप	लखेश्वर बघेल	सोनसाय कश्यप	--	जगमोहन बघेल
(86) जगदलपुर	श्री किरण सिंह देव	जितिन जायसवाल	नवनीत चांद	--	नरेंद्र भवानी
(87) चित्रकोट (अजजा)	श्री विनायक गोयल	दीपक बैज	भरत कश्यप	--	राम मांडवी
(88) दंतेवाड़ा (अजजा)	श्री चेतराम अरामी	छविंद्र महेंद्र कर्मा	बेला तेलाम	--	बालू राम भवानी
(89) बीजापुर (अजजा)	श्री महेश गागड़ा	विक्रम मंडावी	रामधर जुर्री	--	--
(90) कोंटा (अजजा)	श्री सोयम मुका	कवासी लखमा	देवेंद्र तेलाम	--	--

चलो रिश्ते बनाते हैं
आपको ज़ेवर से सजाते हैं
Deepak Advertisers
नई डिजाईन व उम्दा कारीगरी से पीढ़ी दर पीढ़ी
हम आपको संवारते आ रहे हैं..
त्यौहारों के इस मौसम में हम फिर एक बार
आपको सजाने आएं हैं
कुछ नये रिश्ते बनाने आए हैं..
शुभ दीपावली ऑफर
12 नवम्बर 2023 तक
chalo rishte banate hain apko jewar se sajate hain
SUNDAY OPEN
डायमंड एवं गोल्ड ज्वेलरी की हर खरीदी पर पाएं सोने का सिक्का
+
100% एक्सचेंज पुरानी गोल्ड ज्वेलरी पर
जेवर
हर उत्सव के लिए
गंज पारा - दुर्ग
स्टेट बैंक मुख्य शाखा के पास
संपर्क
0788-2214999
9522914999

भाजपा ने क्यों उतारे अपने सांसद

विस चुनाव में उतार दिए 21 सांसद
कहीं यह 2024 की तैयारी तो नहीं
क्षेत्रीय नेताओं से उठ गया भरोसा?

भारतीय जनता पार्टी ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर एक ऐसा दांव खेला है जिससे राजनीतिक विश्लेषक तक चकित हैं. पार्टी ने इन राज्यों में अब तक अपने 21 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है. इसके साथ ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी का अपनी राज्य इकाइयों पर से भरोसा उठ चुका है. स्थानीय नेताओं की वोट हासिल करने की क्षमता को लेकर भी सशंकित है. इसलिए सांसदों को मैदान में उतार कर वह विधानसभा चुनावों को राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित करना चाहती है. जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस रणनीति के पीछे की असली वजह क्या है.

» दीपक रंजन दास

इन विधानसभा चुनावों को इतनी गंभीरता से लेने के पीछे एक ठोस वजह है. राष्ट्रीय स्तर पर जहां भाजपा की कोई काट अभी दूर-दूर तक नजर नहीं आती वहीं राज्यों में उसकी स्थिति के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता. 2014 में जब नरेन्द्र मोदी ने पहली बार सरकार बनाई थी, उस समय देश के सात राज्यों में भाजपा की सरकार थी. ये राज्य थे गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा. पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ वह सत्ता की साझेदार थी. 2018 में जब भाजपा अपने चरम पर थी तब 21 राज्यों में भाजपा या उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकारें थी. पर स्थिति तेजी से बदली और अब सिर्फ 14 ऐसे राज्य हैं, जहां

भाजपा या उसके गठबंधन की सरकार है.

अर्थात पिछले कुछ वर्षों में सात राज्य भाजपा के हाथ से जाते रहे हैं. भाजपा ने इस स्थिति का आकलन किया है और एक ठोस नतीजे पर पहुंच चुकी है. वह इस स्थिति को बदलना चाहती है. स्थानीय नेताओं के वोट हासिल करने की क्षमता को लेकर वह संतुष्ट नहीं है. इसलिए वह राज्यों में नया नेतृत्व पैदा करने की कोशिश करेगी. विशेषज्ञ इसके पीछे तीन अन्य कारण मानते हैं. पहला, इससे सांसदों की लोकप्रियता का अंदाजा हो जाएगा. दूसरा, वोटरों को भी यह संदेश जाएगा कि भाजपा इन चुनावों को लेकर कितना गंभीर है. तीसरा, विधानसभा चुनाव में केन्द्र की झलक ही भाजपा का बेड़ा पार लगा सकती है.

सीधी टक्कर और तीसरी ताकतें

पिछले कुछ चुनावों में भी एक ट्रेंड लगभग साफ हो चुका है. वोटर अब स्पष्ट जनादेश और स्पष्ट प्रतियोगिता तय कर देते हैं. पश्चिम बंगाल में 86 फीसदी वोट तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच बंटे थे जबकि मैदान में कांग्रेस और लेफ्ट भी थे. इसी तरह कर्नाटक में उसका सीधा मुकाबला कांग्रेस से था. दोनों दलों के बीच यहां 80 फीसदी वोटों का बंटवारा हुआ था जबकि मैदान में जनता दल सेकुलर और दूसरी कई छोटी-मोटी पार्टियां भी थीं. हिमाचल में भी 87 प्रतिशत वोट कांग्रेस और भाजपा के बीच बंटे थे जबकि आम आदमी पार्टी और दूसरे उम्मीदवार भी मैदान में थे. गुजरात में आप ने हाई वोल्टेज चुनाव लड़ा था फिर भी 80 फीसद वोट भाजपा और कांग्रेस के बीच बंटे थे. उत्तर प्रदेश में 75 फीसद वोट भाजपा और समाजवादी गठबंधन के बीच ही बंटे थे जबकि मैदान में बसपा और कांग्रेस जैसे दल भी थे.

राज्यों में केन्द्र जैसी स्थिति की ख्वाहिश

राज्यों में क्षेत्रीय दलों का बड़ा प्रभाव होता है. उनकी सीधी टक्कर किस पार्टी से होगी, यही सुनिश्चित कर देती है कि हार या जीत किसकी होगी. राज्यों में न केवल क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला होता है बल्कि नवोदित राष्ट्रीय पार्टियां भी वहां ज्यादा जोर लगाती हैं. जहां तक राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, सभी दलों या उनके समूह का सीधा मुकाबला भाजपा से है. भाजपा चाहती है कि राज्यों में भी यही स्थिति हो. इसलिए उसने अपने सांसदों को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है. इससे विधानसभा चुनावों में केन्द्र सरकार की झलक साफ दिखाई देने लगेगी. यह "वन नेशन-वन इलेक्शन" के भी अनुकूल होगा. इससे पहले भाजपा "मेरी माटी, मेरा देश" अभियान के जरिए भी देश की जनता को सीधे केन्द्र सरकार से जोड़ने की कोशिशें कर चुकी है.

इसलिए पैदा हुई यह स्थिति

जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व विशाल आकार ग्रहण कर लेता है तो उसकी छांव में अन्य नेताओं का कद बहुत छोटा हो जाता है. भाजपा में भी नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो चुका है कि शेष नेताओं के होने तक का अहसास नहीं होता. अधिकांश सांसदों को वहां पड़े-पड़े जंग लग रहा था. उन्हें 2024 के चुनावों के लिए तैयार रखने का सबसे आसान तरीका यही था कि उन्हें विधानसभा चुनावों में उतर दिया जाए. यदि वे अपना जंग झड़ाने में सफल रहे तो न केवल पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी बल्कि लोकसभा के लिए भी पूरी तरह तैयार हो जाएगी. भाजपा वैसे भी विधानसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को लेकर ही मैदान में है.

अरुण साव, विस क्षेत्र लोरमी

विजय बघेल, विस क्षेत्र पाटन

रेणुका सिंह, भरतपुर सोनहत

गोमती साय, विस पत्थलगांव

छत्तीसगढ़ में स्थिति अलग

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में एक साथ चुनाव होने हैं. इनमें से मध्यप्रदेश में सरकार के खिलाफ एंटी इनकमबेंसी फैक्टर काम करता प्रतीत हो रहा है. भाजपा ने यहां अपने सात सांसदों को मैदान में उतारा है. छत्तीसगढ़ में स्थिति अलग है. यहां पिछले चुनाव में भाजपा का एक तरफा सफाया हो गया था. उसके अधिकांश कद्दावर चुनाव हार गए थे. भाजपा यहां अब तक चार सांसदों को टिकट दे चुकी है, यहां भी अधिकांश नेताओं को पिछले लगभग पांच सालों में जंग लग चुका है, इनमें जान फूंकने के लिए भी केन्द्रीय और क्षेत्रीय नेताओं का घालमेल जरूरी था. पर पार्टी ने यह सावधानी भी बरती है कि अधिकांश पुराने चेहरों पर भरोसा किया गया है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही असली मुकाबला है. अन्य दलों की उपस्थिति नाम मात्र ही रहेंगी.

मुख्यमंत्री और गृहमंत्री का है निर्वाचन क्षेत्र
छह में से पांच पर किया था कांग्रेस ने कब्जा
वैशाली में फंसा पेंच, दुर्ग में दांव पर साख
भिलाई में अल्टरनेटिव एमएलए की सुगबुगाहट

वीवीआईपी दुर्ग जिले की

6 सीटों पर घमासान

» डॉ. डी.पी. देशमुख

दुर्ग जिले की छह विधानसभा सीटों पर 17 नवम्बर को मतदान होना है. स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू इसी जिले के निवासी हैं, भूपेश पाटन से तो ताम्रध्वज दुर्ग ग्रामीण से विधायक हैं. भाजपा ने पाटन से जहां सांसद विजय बघेल को सीएम के मुकाबले मैदान में उतारा है वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज का मुकाबला भाजपा के ललित चन्द्राकर से है. अहिवारा की आरक्षित सीट पर भाजपा के पूर्व विधायक कोर्सेवाड़ा के मुकाबले कांग्रेस ने भिलाई-चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे को मैदान में उतारा है. दुर्ग शहर से वर्तमान विधायक अरुण वोरा को भाजपा के गजेन्द्र चुनौती देंगे. भिलाई नगर से युवा विधायक देवेन्द्र यादव एक बार फिर भाजपा के कद्दावर नेता प्रेमप्रकाश पाण्डेय का मुकाबला करने जा रहे हैं. वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन की मृत्यु के बाद से यह सीट रिक्त थी जिसपर पांच बार के पार्षद रिकेश सेन भाजपा के प्रत्याशी हैं, इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के मुकेश चन्द्राकर से होगा.

दुर्ग जिले को वीवीआईपी जिला माना जाता है. मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री का गृह जिला होने के अलावा यह भाजपा के कद्दावर नेता प्रेमप्रकाश पाण्डेय का भी निवास स्थान है. यहां की छह में से केवल एक अहिवारा सीट आरक्षित है. 2018 के विधानसभा चुनाव में भारी उलटफेर करते हुए कांग्रेस ने जिले की छह में से पांच सीटों पर विजय हासिल कर ली थी. इस जिले की सभी सीटों पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है. इनमें से एकमात्र भिलाई नगर विधानसभा की सीट ऐसी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां कोई भी प्रत्याशी लगातार दो बार नहीं जीतता. इस बार भाजपा इसी उम्मीद में है कि यह कयास सही साबित हो.

पाटन में सीएम का मुकाबला करेंगे सांसद

भूपेश बघेल

विजय बघेल

इस बार के चुनाव में पाटन में हाईवोल्टेड ड्रामा देखने को मिल सकता है. यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुकाबला इसी क्षेत्र के निवासी तथा दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल से है. छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की ओर से बनाई गई हमर राज पार्टी ने अपने अध्यक्ष बीएस रावटे को भी इसी सीट पर चुनावी मैदान में उतारा है. 2018 में यहां कुल 52 प्रतिशत वोट पड़े थे और भूपेश बघेल ने भाजपा के मोतीलाल साहू को मामूली अंतर से हराया था. पर इसके बाद समीकरण तेजी से बदले. भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने और फिर छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रतिष्ठित मुकाम दिलाने में उनकी सफलता अब सिर चढ़ कर बोल रही है. माना जाता है कि उनका

मुकाबला करना किसी भी प्रत्याशी के लिए खुदकुशी करने जैसा है.

भूपेश बघेल न केवल छत्तीसगढ़ियावाद बल्कि किसानों की सरकार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं. धान खरीदी, गोधन न्याय और नरवा-गरुवा-घुरवा-बाड़ी, आदि योजनाओं के चलते ग्रामीणों, विशेषकर किसानों के बीच उनकी अच्छी साख है. पिछले पांच साल में पाटन क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का लाभ भी उन्हें मिलेगा. अभी उनका केवल एक ही कार्यकाल पूरा हुआ है इसलिए एंटी इन्कमबेंसी जैसी भी कोई बात नहीं है. पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होने के कारण हो सकता है चुनाव के दौरान वे पाटन को ज्यादा समय न दे पाएं पर इसका ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद नहीं है.

भूपेश का सीधा मुकाबला भाजपा के सांसद विजय बघेल से है. विजय बघेल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2000 में की थी. उन्होंने पार्षद का पहला चुनाव स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीता. 2003 में वे राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो गये और पाटन से चुनाव लड़े. इस चुनाव में उनकी हार हुई, इसके बाद वे भाजपा में शामिल हो गए. 2008 के चुनावों में उन्होंने पाटन विधानसभा सीट पर भूपेश बघेल को करारी शिकस्त दी, इसके बाद उन्हें संसदीय सचिव बनाया गया. वे भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी रहे हैं, 2013 का चुनाव वे भूपेश बघेल से हार गए. पार्टी ने इसके बाद 2019 में उन्हें दुर्ग संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा, कांग्रेस की प्रतिमा चन्द्राकर को हरा कर वे लोकसभा में पहुंच गए. पर इस बार उनका मुकाबला प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे से है. किसान पहले ही भाजपा से नाराज चल रहे हैं, उन्हें क्षेत्र में अपनी सक्रियता, मिलनसार व्यक्तित्व, स्थानीय समस्याओं तथा शराब बंदी जैसे मुद्दों पर निरंतर संघर्ष का लाभ मिल सकता है. वे भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक भी हैं.

भिलाई नगर में फिर भिड़ेंगे देवेन्द्र-प्रेमप्रकाश

देवेन्द्र यादव

प्रेमप्रकाश पाण्डेय

भिलाई नगर विधानसभा सीट पर भाजपा के पूर्व मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय पिछली बार चुनाव हार गए थे. कांग्रेस के युवा नेता एवं महापौर देवेन्द्र यादव ने उन्हें 2849 मतों से पराजित कर दिया था. इसके साथ ही देवेन्द्र देश के सबसे कम उम्र के विधायक बन गए थे. चुनाव जीतने के बाद देवेन्द्र लगातार लोगों के बीच सक्रिय रहे. भिलाई के लोगों के लिए यह एक नया अनुभव था. पहली बार ऐसा हुआ था कि विधायक हर समय उपलब्ध था. ईडी छापों के बाद भी वह अपनी हर बात लोगों के साथ साझा करता था. उनके सुख-दुःख में शरीक होते रहे. देवेंद्र को अपनी बिंदास छवि के साथ ही अपने कार्यकाल में शहर व प्रदेश में हुए विकास कार्यों का लाभ मिलेगा, युवाओं के बीच भी उनकी अच्छी पकड़ है जिसका लाभ उन्हें मिल सकता है.

वहीं भाजपा प्रत्याशी प्रेमप्रकाश पाण्डेय एक वरिष्ठ नेता हैं, मध्यप्रदेश के समय से राजनीति में सक्रिय श्री पाण्डेय मध्यप्रदेश विधानसभा में भी मंत्री रहे हैं. वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और रमन सरकार में मंत्री भी. उनकी छवि देवेन्द्र से ठीक उलट है. उनका एक अपना कॉकस है जिसके बाहर बहुत कम लोगों से वो खुलकर मिलते हैं. उनके आसपास खास लोगों का एक घेरा होता है जिसे पार करना आम जनता के लिए सम्भव नहीं. पिछले पांच वर्षों में वे लोगों के बीच बहुत कम आए हैं या किसी मुद्दे को लेकर सक्रिय दिखे हैं. प्रेमप्रकाश ने भी अपने कार्यकाल में कई बड़ी योजनाओं को पूरा किया था और पानी वाले बाबा के रूप में शोहरत पाई थी. भाजपा के पारम्परिक वोटों के अलावा उन्हें यूपी-बिहार के लोगों का समर्थन मिल सकता है, श्री पाण्डेय आठवीं बार चुनाव मैदान में हैं.

वैसे भी भिलाई का रिकार्ड है कि छत्तीसगढ़ बनने के समय से लेकर अब तक कोई भी विधायक लगातार दो चुनाव नहीं जीत पाया. राज्य गठन के समय बीडी कुरैशी विधायक थे जिसे 2003 में श्री पाण्डेय ने मात दी. 2008 में पुनः कुरैशी जीत गए. 2013 में पाण्डेय चुनाव जीत गए पर 2018 में उन्हें फिर पराजय का मुंह देखना पड़ा.

दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज के मुकाबले में ललित

ताम्रध्वज साहू

ललित चन्द्राकर

दुर्ग ग्रामीण एक और प्रतिष्ठापूर्ण सीट है जहां से मौजूदा गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की साख दांव पर है. उनका मुकाबला भाजपा के युवा प्रत्याशी ललित चन्द्राकर से है. कांग्रेस की मौजूदा सरकार को भाजपा कानून व्यवस्था कि स्थिति को लेकर लगातार घेरती रही है. इसके अलावा राजस्व अधिकारियों की मनमानी, केन्द्रीय सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी जैसे मामलों से उभरा आक्रोश उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है. 1990 के दशक में जिला साहू संघ से शुरू हुआ उनका सार्वजनिक जीवन अब तक बेदाग रहा है. 1998 में वे पहली बार धमधा से विधायक चुने गए. राज्य गठन के बाद वे जोगी सरकार में मंत्री बने, 2003 में उन्होंने धमधा सीट से दोबारा जीत हासिल की. 2008 में उन्होंने बेमेतरा से विधानसभा चुनाव जीता. 2013 का विधानसभा चुनाव वे हार गए पर इसके तुरंत बाद 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की सरोज पाण्डेय को पराजित कर संसद पहुंच गए. 2018 में वे दुर्ग ग्रामीण सीट से विधायक और भूपेश सरकार में मंत्री बने.

भाजपा ने इस सीट पर ललित चन्द्राकर को प्रत्याशी बनाया है, पिछले लगभग बीस सालों से वे भाजपा में सक्रिय हैं. पहले संगठन और फिर भाजपा के विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं. उन्हें भाजपा के कद्दावर नेता ताराचंद साहू का शिष्य होने के अलावा जातिगत समीकरणों का का लाभ मिल सकता है. प्रीतपाल की गिरफ्तारी से उभरा आक्रोश उनके हक में जा सकता है. क्षेत्र के नगर निगम और नगर पंचायत में कांग्रेस का वर्चस्व होने और वरिष्ठ मंत्री से मुकाबला उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी.

वैशाली नगर में रिकेश का मुकाबला मुकेश से

मुकेश चन्द्राकर

रिकेश सेन

वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही नए उम्मीदवारों को मौका दिया है. 2018 के चुनाव में यह दुर्ग जिले की इकलौती विधानसभा सीट थी जिसपर भाजपा की जीत हुई थी. भाजपा के विद्यारतन भसीन ने कांग्रेस प्रत्याशी बदरुद्दीन कुरैशी को इस सीट पर पराजित किया था, भसीन के निधन के बाद यह सीट फिलहाल रिक्त है जिसपर भाजपा ने पांच बार के पार्षद रिकेश सेन को अपना प्रत्याशी बनाया है. वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चन्द्राकर को मौका दिया है. दोनों पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं.

रिकेश सेन के बारे में कहा जाता है कि उसे जहां से खड़ा करो, वहीं से पार्षद का चुनाव जीत जाता है. रिकेश को भाजपा में सांसद सरोज पाण्डेय खेमे का माना जाता है, दोनों की कार्यशैली भी एक जैसी है. धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी देने के अलावा वे नाटकीय आयोजन करने के लिए भी जाने जाते हैं. अधिकारी-कर्मचारियों से काम करवाने का भी उनका अपना अलग अंदाज है. उन्हें टिकट दिये जाने को लेकर भाजपा में असंतोष के स्वर फूटे थे जो शांत तो हो गए हैं पर अभी खत्म नहीं हुए हैं. रिकेश ने पार्षद के चुनाव भले ही अपने दम पर जीते हों पर इस बार बात विधानसभा की है जहां संगठन की ताकत के बिना जीत की डगर बेहद मुश्किल हो सकती है.

वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को उतारा है. मुकेश की कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी स्वीकार्यता है. वैशालीनगर एक श्रमिक बहुल क्षेत्र है जहां लगभग सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं इसलिए जातिगत समीकरण यहां ज्यादा काम नहीं करते. उन्हें भूपेश सरकार की उपलब्धियों के साथ ही छत्तीसगढ़ियावाद का लाभ मिल सकता है.

दुर्ग शहर में वोरा से भिड़ेंगे गजेन्द्र

अरुण वोरा

गजेन्द्र यादव

दुर्ग शहर की प्रतिष्ठित सीट पर इस बार सिटिंग एमएलए अरुण वोरा को भाजपा प्रत्याशी गजेन्द्र यादव का सामना करना है. सातवीं बार चुनाव मैदान में उतारे गए अरुण वोरा इससे पहले तीन बार चुनाव हार चुके हैं. हालांकि उन्होंने 2013 और 2018 विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की है. पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा की महापौर चन्द्रिका चन्द्राकर को 21 हजार से अधिक मतों से पराजित किया था. छग ब्रेवरेज कार्पोरेशन के अध्यक्ष रहे वोरा लगातार अपने चुनाव क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और लोगों को सहज उपलब्ध हैं, इसके अलावा उन्हें अपने पूर्व मुख्यमंत्री एवं बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा की विरासत का भी लाभ मिलता है. भाजपा ने इस बार उनके मुकाबले गजेन्द्र यादव को प्रत्याशी बनाया है. पूर्व पार्षद होने के अलावा गजेन्द्र की युवाओं के बीच अच्छी पकड़ है, उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह बिसराराम यादव का पुत्र होने का लाभ भी मिल सकता है. संघ को पहली बार अपने बीच का कोई प्रत्याशी मिला है, इसलिए उम्मीद है कि इस बार वे एड़ी-चोटी का जोर लगा देंगे. जातिगत समीकरण का भी उन्हें लाभ मिल सकता है.

अहिवारा में हैट्रिक से चूकी थी भाजपा

निर्मल कोसरे

डोमनलाल कोर्सेवाड़ा

2008 के परिसीमन में पाटन विधानसभा और धमधा को मिलाकर बनाए गए अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के गठन के बाद से यहां भाजपा का कब्जा रहा है. इस विधानसभा को अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए आरक्षित किया गया. यह जिले के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्रों में से एक है. साल 2008 में भाजपा के डोमन लाल कोर्सेवाडा यहां से पहले विधायक चुने गए थे. 2013 में भाजपा के ही सांवलाराम डहारे यहां से विधायक चुने गए. 2018 में भाजपा यहां हैट्रिक मारने से चूक गई जब कांग्रेस के गुरू रुद्र कुमार ने सीटिंग विधायक सांवलाराम डाहरे को 31 हजार 687 वोटों के अंतर से हराया दिया. गुरू रुद्र कुमार को इसके बाद पीएचई मंत्री बनाया गया.

इस बार इस सीट पर कांटे का मुकाबला होगा. कांग्रेस ने इस बार यहां से भिलाई-चरोदा महापौर निर्मल कोसरे को मौका दिया है. भाजपा ने इस सीट पर डोमनलाल कोर्सेवाड़ा पर एक बार फिर भरोसा जताया है. कोर्सेवाड़ा इस सीट के प्रथम विधायक रहे हैं. इस विधानसभा में सतनामी समाज के मतदाताओं की संख्या अधिक है इसके अलावा साहू, कुर्मी, अन्य पिछड़ा वर्ग मतदाता भी हैं.

निर्मल कोसरे युवा, सक्रिय और जुझारू नेता हैं. दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष रहे कोसरे इससे पहले गनियारी के पार्षद थे. गठन के 21 साल बाद जब पहली बार भिलाई-3 चरोदा निगम में कांग्रेस का परचम फहराया तो निर्मल को इसका अध्यक्ष चुना गया. अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हुए वे एक अच्छी छवि बनाने में सफल रहे, उनकी चर्चा मानवीय आधार पर लिये गये फैसलों के लिए भी होती रही है, उन्हें कांग्रेस सरकार के कामकाज का लाभ मिल सकता है. वहीं कोर्सेवाड़ा ने बतौर शिक्षक इस अंचल में काफी नाम कमाया था, बतौर विधायक भी वे काफी लोकप्रिय रहे. सामाजिक गतिविधियों में उनकी लगातार सक्रिय भागीदारी रही है, यदि मोदी मैजिक चला तो यह सीट एक बार फिर भाजपा की हो सकती है.

सरला कोसरिया

चातुरी नंद

संपत अग्रवाल

देवेन्द्र बहादुर सिंह

अलका चन्द्राकर

द्वारिकाधीश यादव

योगेश्वर राजू सिंहा

डॉ. रश्मि चन्द्राकर

जातिगत समीकरणों को किया दरकिनार

कांग्रेस अब भी पुराने फार्मूले पर कायम

चारों सीटों पर बारी-बारी होती है हारजीत

भाजपा ने तोड़ी प्रत्याशी चयन की परम्परा

» मनोज शंकर

भाजपा ने महासमुन्द जिले की सीटों पर जातिगत समीकरणों को हाशिए पर धकेल दिया है. यहां की चारों विधानसभा सीटों पर उसने क्रॉस उम्मीदवार खड़े किये हैं. इसका तात्पर्य यह है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व जरूर दिया गया है पर उनकी सीटें बदल दी गई हैं. राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो भाजपा जातिगत मतगणना एवं आरक्षण के खिलाफ दिखाई देती है. इस जिले में महासमुन्द, सरायपाली, बसना और खल्लारी-बागबाहरा आते हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन चारों सीटों पर जीत दर्ज की थी.

महासमुंद जिले की चारों सीटें पिछड़ा वर्ग बहुल हैं. महासमुंद जिले में कुर्मी, साहू, कोलता, अघरिया वर्ग का वर्चस्व है, लिहाजा टिकट वितरण में पार्टियां जातिगत समीकरणों का ध्यान रखती रहीं हैं. ओबीसी के बाद जिले में आदिवासियों की बहुलता है. सरायपाली विधानसभा के कुछ क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग की बहुलता है, जिसके आधार पर सीट को आरक्षित कर दिया गया है.

भाजपा ने महासमुंद से कलार समाज के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया है. यह क्षेत्र कुर्मी-साहू बहुल है. खल्लारी-बागबाहरा के आदिवासी-साहू-अघरिया बहुल क्षेत्र में भाजपा ने कुर्मी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है. बसना के कोलता-अघरिया एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र में अग्रवाल उम्मीदवार को टिकट दिया है, तो सरायपाली के गांड़ा बहुल आरक्षित सीट पर सतनामी समाज के अभ्यर्थी को चुनावी मैदान में उतारा है.

कांग्रेस ने महासमुंद से कुर्मी, बसना के कोलता-अघरिया एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी-महल, सरायपाली के गांड़ा बहुल आरक्षित सीट पर गांड़ा समाज के अभ्यर्थी को ही प्रत्याशी बनाया है. सिर्फ एक सीट खल्लारी-बागबाहरा में यादव समाज के प्रत्याशी उतारा गया है. यह सीट आदिवासी-साहू-अघरिया बहुल है. कांग्रेस ने पहली बार महासमुंद व सरायपाली सीट से महिलाओ को अवसर दिया है. महासमुंद से विधायक विनोद चंद्राकर का टिकट काटकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर व सरायपाली से मौजूदा विधायक किस्मतलाल नंद की जगह चातुरी नंद को उम्मीदवार बनाया गया है. बसना से कांग्रेस ने देवेन्द्र बहादुर सिंह और खल्लारी से द्वारिकाधीश को प्रत्याशी बनाया है. वहीं भाजपा ने भी महासमुन्द जिले की दो सीटों पर महिलाओं को मौका दिया है. इनमें सरायपाली से सरला कोसरिया तथा खल्लारी से अलका चन्द्राकर शामिल हैं. बसना से भाजपा ने संपत अग्रवाल को और महासमुन्द से योगेश्वर राजू सिन्हा को टिकट दिया है.

विधानसभा	भाजपा	कांग्रेस
39. सरायपाली	सरला कोसरिया	चातुरी नंद
40. बसना	संपत अग्रवाल	देवेन्द्र बहादुर सिंह
41. खल्लारी	अलका चन्द्राकर	द्वारिकाधीश यादव
42. महासमुन्द	योगेश्वर राजू सिन्हा	डॉ रश्मि चन्द्राकर

इन सीटों पर हार-जीत का है रोचक इतिहास

महसमुन्द जिले के चार विधानसभा सीटों के बारे में यह कहा जाता है कि यहां प्रत्याशी या पार्टी की जीत बारी-बारी से होती है – अर्थात एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा. पिछले चुनाव में भाजपा को इन चारों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था. इसलिए उसे लगता है कि इस बार वह सभी चार सीटों पर जीत हासिल कर लेगी. उल्लेखनीय है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महासमुंद जिले में शानदार प्रदर्शन किया और सभी चार सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था. इसके पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चारों सीट हार चुकी थी. 2008 में महासमुंद जिला के चारों सीट पर कांग्रेस और 2003 में जिले के चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है.

तीनों सीटों पर घमासान

» अरमान अश्क

बालोद जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में राजनीति की अपनी अलग चाल है. भाजपा हो या कांग्रेस, किसी के लिए भी यहां से प्रत्याशी तय करना कठिन होता है. ये तीन सीटें हैं संजारी बालोद, डौण्डीलोहारा और गुण्डरदेही. तीनों सीटों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है जिसे छीनने की पूरी कोशिश भाजपा कर रही है. इनमें डौण्डीलोहारा एकमात्र ऐसी सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है. डौण्डीलोहारा का अपना एक अलग इतिहास है जहां राजपरिवार और आदिवासी नेतृत्व के बीच ही हार-जीत होती रही है. गुण्डरदेही को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है. यहां कभी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (अविभाजित दुर्ग जिला) वासुदेव चन्द्राकर की ही चलती थी. उन्हें कांग्रेस का चाणक्य माना जाता था. आज भी उनका प्रभाव यहां देखा जाता है. संजारी बालोद को भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है. यहां का पिछला चुनाव कांग्रेस की महिला प्रत्याशी ने जीता था.

इन तीनों विधानसभाओं पर इस बार कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है. तीनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायकों को रिपीट किया है. संजारी बालोद से संगीता सिन्हा प्रत्याशी हैं. भाजपा ने उनके खिलाफ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश यादव को मैदान में उतारा है. डौण्डीलोहारा की बात करें तो कांग्रेस ने यहां से भूपेश सरकार में मंत्री रही अनिला भेंडिया को रिपीट किया है जबकि भाजपा से देवलाल ठाकुर उन्हें चुनौती देंगे. इस सीट पर महाराष्ट्र के राजपरिवार की छाया देवी टेकाम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है. इसलिए यह मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है. गुण्डरदेही से सिटिंग एमएलए कुंवर सिंह निषाद एक बार फिर मैदान में हैं. पिछले बार उन्होंने इस सीट पर एकतरफा जीत हासिल की थी. इस बार उनका मुकाबला भाजपा के पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू से होगा. तीनों ही मुकाबले बेहद रोचक होंगे.

डौंडीलोहारा में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार

अनिला भेड़िया

देवलाल ठाकुर

डौंडी लोहारा की आरक्षित सीट पर इस बार त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हैं. इस सीट पर अब तक लोहारा राज परिवार या फिर आदिवासी नेता झुमुक लाल भेंडिया के परिवार का कब्जा रहा है. कांग्रेस ने यहां से वर्तमान विधायक एवं भेंडिया परिवार की बहू अनिला भेंडिया को दोबारा प्रत्याशी बनाया है. वे भूपेश सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री थीं. भाजपा की ओर से देवलाल ठाकुर मैदान में हैं. देवलाल ठाकुर हल्बा समाज से आते हैं. मूलत: कांग्रेसी देवलाल पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी बन गए थे.

उन्होंने 21368 मत मिले थे. इसके बाद उनका भाजपा प्रवेश हुआ और भाजपा ने इस बार उन्हें टिकट दिया है.

इतिहास की बात करें तो 1957 में रानी झमित कुंवर देवी पहली बार विधायक चुनी गईं. 1962 से 1985 तक लगातार पांच बार कांग्रेस के कद्दावर नेता झुमूक लाल भेंडिया निर्वाचित होते रहे. 1985 से 90 तक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जनक लाल ठाकुर ने इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया. 1990 से 92 तक पुन: श्री भेंडिया इस क्षेत्र के विधायक रहे. भाजपा के पास यह सीट 2003 में आई जब राज परिवार के लाल महेंद्र टेकाम ने यहां से चुनाव जीता. 2008 में दोबारा इस सीट पर भाजपा की जीत हुई और नीलिमा टेकाम विधायक बनीं.

2013 में कांग्रेस ने भेंडिया परिवार की बहू अनिला भेंडिया को अपना प्रत्याशी बनाया. अनिला ने भाजपा प्रत्याशी होरीलाल रावटे को 19735 मतों से पराजित कर यहां जीत दर्ज की. 2018 के चुनाव में अनिला ने भाजपा प्रत्याशी लाल महेंद्र सिंह को भी 33103 मतों से पराजित कर दिया. कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही अनिला भेड़िया को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई.

2023 में कांग्रेस ने पुनः अनिला पर भरोसा किया है. पर इस बार पूर्व कांग्रेसी देवलाल ठाकुर भाजपा प्रत्याशी के रूप में उन्हें चुनौती दे रहे हैं. निर्दलीय के रूप में अपनी ताकत दिखा चुके देवलाल इस बार अनिला को कड़ी टक्कर देंगे. इस मुकाबले को और रोचक बना रही है महाराष्ट्र राजघराने की छाया देवी टेकाम. उनके पिता स्व. फतेह लाल शाह महाराष्ट्र के चंद्रपुर से विधायक रह चुके हैं. उनके पति लाल भूपेंद्र सिंह डौंडी लोहारा नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं. उनका हाल ही में निधन हुआ है.

देवलाल ठाकुर हल्बा समाज से आते हैं. वनांचल क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है. 2013 में बालोद जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए और अनेक विकास कार्य किए. वे दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्र में लाल पानी प्रदूषण आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं. पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने 21 हजार से भी ज्यादा मत प्राप्त किये थे.

संजारी बालोद में संगीता बनाम राकेश

संगीता सिन्हा

राकेश यादव

संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है. यहां कांग्रेस ने अपने विधायक संगीता सिन्हा पर ही दोबारा भरोसा जताया है. तेज तर्रार संगीता सिन्हा की न केवल सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिलाओं के बीच अच्छी पकड़ है बल्कि उन्हें काम करवाना भी आता है. उनपर एकमात्र आरोप यह है कि वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर नहीं चलतीं. प्रत्याशी चयन के दौरान भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनके खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली थी.

जहां तक प्रदर्शन की बात है तो संगीता सिन्हा को श्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है. 2018 के चुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पवन साहू को 27,498 मतों से पराजित किया था. अपने कार्यकाल में संगीता ने अनेक विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया. विधानसभा में भी वे मुखर रहीं और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करती रहीं. पर इस बार उनकी राह आसान नहीं है. इस बार भाजपा ने राकेश यादव को प्रत्याशी बनाया है. राकेश यादव छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे हैं. साथ ङई वे संघ और भाजपा के सांगठनिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं. उन्हें पोलिंग बूथ स्तर पर काम करने का भी अनुभव है. मंडल स्तर पर महामंत्री और दो बार अध्यक्ष रहे राकेश ने प्रदेश मंत्री के दायित्व का भी निर्वहन किया है. 2004 में उन्हें बालोद नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया था. इस दौरान उन्होंने अनेक विकास कार्य कराए.

गुण्डरदेही में होगी निषाद बनाम साहू

कुंवर सिंह निषाद

वीरेन्द्र साहू

गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है. एक समय ऐसा था जब राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले दाऊ वासुदेव चंद्राकर जिसके सिर पर हाथ रखते थे वही चुनाव जीतता था. दाऊजी नहीं रहे परंतु उनका प्रभाव क्षेत्र कम नहीं हुआ है. 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हाई कमान ने क्षेत्र के लोक कलाकार कुंवर सिंह निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया था. उन्होंने रिकार्ड मतों से चुनाव जीतकर सबको हैरान कर दिया था. उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता स्व. ताराचंद साहू के पुत्र एवं भाजपा प्रत्याशी दीपक साहू को 55 हजार से भी अधिक मतों से पराजित कर दिया था. कांग्रेस ने कुंवर सिंह को पुनः इस क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है. इस बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है. भाजपा ने एक बार फिर वीरेन्द्र साहू पर भरोसा जताया है. वीरेंद्र साहू ने 2008 के चुनाव में भाजपा को पहली बार गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र से जीत दिलाई थी. उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता घनाराम साहू को 2585 मतों से पराजित कर यह सीट जीती थी.

आखिरी समय में तय हो पाते हैं प्रत्याशी

संजारी बालोद, गुण्डरदेही में सीधा मुकाबला

डौंडीलोहारा में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार

भाजपा के आरोप पत्र में नहीं है दम

रोहिंग्या-धर्मांतरण पर फैला रही भ्रम

सत्ता गंवाने के बाद से निठल्ली बैठी भाजपा में कुछ ही महीने पहले प्राण लौटे हैं. वह राज्य के भिन्न-भिन्न हिस्सों में अलग-अलग भ्रम फैला कर जनता को भरमाने की कोशिश कर रही है. जितना बड़ा झूठ वह कांग्रेस राज में धर्मांतरण को सरकारी संरक्षण को लेकर बोल रही है, लगभग उसी स्तर का झूठ वह रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी बोल रही है. जिन घटनाओं के साम्प्रदायिक होने का भाजपा दावा कर रही है, वो भी आपसी झगड़े से ही जुड़े हुए हैं. इसमें किसी भी समाज की कोई भूमिका नहीं थी. इन मामलों को लेकर स्वयं केन्द्रीय गृहमंत्री झूठ बोल गए.

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

भाजपा ने कवर्धा में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का आरोप भूपेश सरकार पर लगाया है. यहां गन्ने की खेती और गुड़ बनाने के कारोबार से जुड़े अधिकांश परिवार मुसलमान हैं. पर ये कोई बांग्लादेश से भगाए गए रोहिंग्या नहीं हैं बल्कि पिछले लगभग ढाई दशक से यहां बसे हुए हैं. इन सभी का मूल राज्य उत्तर प्रदेश है. गन्ने की खेती और गुड़ बनाने के कौशल के चलते वे रोजगार की तलाश में यहां आ बसे हैं. वैसे भी छत्तीसगढ़ एक भू-बद्ध (लैंड लॉक्ड) राज्य है. छत्तीसगढ़ की कोई भी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती. रोहिंग्या मुसलमानों को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रोकना केन्द्र की जिम्मेदारी है. रोहिंग्या मुसलमानों को कई राज्य पार करके छत्तीसगढ़ आना होगा. इनमें से अधिकांश में भाजपा की सरकारें हैं.

एक ऐसा ही आरोप भाजपा बस्तर में धर्मांतरण को लेकर लगाती है. बस्तर में ईसाइयों की गतिविधियां पिछले कई दशकों से जारी है. इसमें अभूतपूर्व तेजी तब आई जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी. आंकड़े बताते हैं कि रमन सरकार के 15 सालों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुए और नए चर्चों की स्थापना हुई. पर कभी भी आदिवासी समुदाय और ईसाइयों के बीच टकराहट नहीं हुई. भाजपा की सरकार जाते ही आदिवासियों ने ईसाइयों का जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया. उन्हें अपने मृतकों के शव दफनाने के लिए स्थान देने से इंकार कर दिया. कहा गया कि इससे आदिवासियों के देवताओं की शक्ती क्षीण होती है. इन हिंसक झड़पों में दोनों ही तरफ आदिवासी थे. यह आग क्यों और किसके द्वारा लगाई गई, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है. कहीं ऐसा न हो कि बस्तर और सरगुजा दूसरा मणिपुर न बन जाए. वैसे यह मुद्दा जनमानस में घर कर गया है. देखना यह है कि इसमें भाजपा को कितना फायदा मिलेगा.

जब सफेद झूठ बोल गए गृहमंत्री

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साजा प्रत्याशी के नामांकन रैली में शामिल होने के बाद यहां भ्रम फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. अव्वल तो लोगों की समझ में यही नहीं आया कि गृहमंत्री ने बिरनपुर के ईश्वर साहू को इतना महत्व क्यों दिया कि उनके नामांकन रैली में शामिल हुए. ईश्वर साहू कोई स्थापित राजनेता नहीं है. उनके पुत्र की कुछ समय पहले आपसी विवाद में कुछ युवकों ने हत्या कर दी थी. गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार आरोपियों को संरक्षण दे रही है. जबकि हकीकत यह है कि बिरनपुर हादसे के बाद राज्य शासन ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी थी. न केवल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था बल्कि यहां किसी भी तरह के उपद्रव को रोकने में भी सरकार सफल रही थी. दरअसल साजा से ईश्वर साहू और कवर्धा से विजय शर्मा को प्रत्याशी बनाया ही इसलिए गया है कि यहां भाजपा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा ले सके. कांग्रेस ने शाह पर राज्य का साम्प्रदायिक माहौल खराब करने और धार्मिक उन्माद पैदा करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत भी की है.

भाजपा प्रत्येक ऐसे मामले को साम्प्रदायिक बताने की कोशिश करती रही है जिसमें एक पक्ष में कोई अल्पसंख्यक हो. जबकि हकीकत यही है कि ये हमले किसी कौम पर नहीं बल्कि व्यक्तिविशेष पर हुए. इससे पहले दुर्ग भिलाई में मूर्ति खंडित करने की कुछ घटनाओं को भी साम्प्रदायिक बताने की कोशिश की गई पर जब असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार पाया गया तो भाजपा का मुंह बंद हो गया. इसी तरह खुर्सीपार में मलकीत सिंह की हत्या को भी साम्प्रदायिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई पर जैसी ही वास्तविकता सामने आई, भाजपा को सांप सूंघ गया.

पीएससी घोटाले की यह है हकीकत

आईएएस को तिलांजलि देकर शिक्षक का पेशा अपनाने वाले मोटिवेशनल गुरू विकास दिव्यकीर्ति की मानें तो छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की पीएससी परीक्षा है. दिव्यकीर्ति यूपीएससी की कोचिंग चलाते हैं. विगत 4-5 सालों में सीजी पीएससी में चयनित होने वाले अधिकांश अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं. इनमें भी एससी, एसटी और ओबीसी की संख्या ज्यादा है. भाजपा के पेटदर्द का यही कारण है. छत्तीसगढ़ में पीएससी लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को इंटरनेट पर डाल दिया जाता है जिसकी जांच कोई भी कर सकता है. साक्षात्कार की व्यवस्था भी ऐसी है कि ये तक पता नहीं होता कि किस अभ्यर्थी का साक्षात्कार कौन लेगा. प्राप्तांकों की सूची पर हस्ताक्षर करने से पहले कोई भी साक्षात्कार लेने वाला कमरे से बाहर नहीं निकल सकता.

भाजपा के आरोपों की पड़ताल में पता चला कि पीएससी चेयरमेन टामन सिंह सोनवानी के एकमात्र रिश्तेदार का ही चयन पीएससी में हुआ है. अफवाह फैलाई गई कि पांच रिश्तेदार का चयन हुआ है. कहा यह भी गया कि सोनवानी को इसी गड़बड़ी के चलते हटाया गया है. सच्चाई यह है कि सोनवानी ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर अवकाश प्राप्त किया है. जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ वे सभी यूपीएससी

चुनाव के मद्देनजर गढ़े गए सभी मुद्दे
न तो छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या का वास
न ही साम्प्रदायिक फसाद
पीएससी में घोटाले का सबूत नहीं

की कोचिंग करने के साथ ही पिछले 7-8 सालों से लगातार परीक्षा दे रहे हैं. पिछले पांच साल में किसी भी मंत्री या विधायक के रिश्तेदार का चयन पीएससी में नहीं हुआ. भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैला रही है. अपनी मेहनत से यह परीक्षा पास करने वालों की मेहनत का उपहास कर रही है. यह मुद्दा भी जनमानस में चर्चा का विषय है. देखना यह लाजिमी होगा कि भाजपा को चुनाव में कहां तक सफलता मिलती है.

धर्मांतरण का इलाज

सनातन धर्म के वर्ण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था के चलते धर्मांतरण होता है. भारत के नागरिक खासकर पिछड़ी जाति के लोग सामाजिक दायरे में बंधे हुए हैं. जो जाति से बाहर नहीं आना चाहते, वे लोग भला क्यों धर्म परिवर्तन करने में मजबूर हो जाते हैं? इसका मूल कारण जाति व्यवस्था में छूआछूत का होना तथा आर्थिक रूप से कमजोर होना. राहुल गांधी ने घोषणा किया कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर तुरंत जाति जनगणना तथा आर्थिक सर्वेक्षण करायी जावेगी. निश्चित ही जाति गणना से सरकार में पिछड़ी जाति का भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होगा एवं आर्थिक सर्वेक्षण करने पर यदि सरकार आर्थिक रूप से पिछड़ों को ध्यान में रखकर योजना बनायी जाती है तो धर्मांतरण पर रोक लग सकती है.

उर्मिला मेमोरियल
सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल
UMH
सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा
सेवा एवं समर्पण के साथ
सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के एक वर्ष पूर्ण
उद्घाटन एवं शुभारंभ
कार्डियेक सर्जरी विभाग
हृदय रोग सर्जरी हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक
नि:शुल्क इको जांच
नि:शुल्क एण्डोस्कोपी
नि:शुल्क फाइब्रोस्कैन
नि:शुल्क
Uro Flowmetry Test (UFT)
नि:शुल्क EEG टेस्ट
आभार एवं धन्यवाद...
सेंटर फॉर एन्टी
रिफ्लक्स सर्जरी,
हाईट्स हार्निया एवं
GERD मरीजों हेतु
सेंटर फॉर
ब्रेन स्ट्रोक एवं हेड
इन्ज्युरी मैनेजमेंट
जांच पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें :
0771-4088820, 9109125524
नहर रोड, भाठागांव, रायपुर (छ.ग.)

अधिक जानकारी
के लिए संपर्क करें:-

79990-01239, 94790-43349
99814-91499, 93025-44701

- आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ
- हो सकता है राजनीतिक नुकसान
- सहज नहीं है कर्जमाफी का गणित
- साढ़े तीन दशक पहले पड़ी थी नींव

किसानों की कर्जमाफी

भूपेश से भिड़े रमन

विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बीच घमासान शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो एक बार फिर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा. इस पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा है कि पांच साल में सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि छत्तीसगढ़ के किसान दोबारा कर्ज से लद गए. राजनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि इस घोषणा से भूपेश बघेल ने फिर से एक मास्टर स्ट्रोक खेला है. यह "अबकी बार 75 पार" के चुनावी नारे के अनुकूल भी है. इससे भूपेश को राजनीतिक बढ़त मिल गई है.

» भूपेन्द्र वर्मा

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने पिछले चुनाव में भी कर्जमाफी का ऐलान किया था. सरकार बनते ही सरकार ने अपना वायदा पूरा भी कर दिया था. इसके साथ ही सरकार ने किसानों का भरोसा भी जीत लिया था. 2018 में भाजपा का सूपड़ा साफ कर सत्ता में आई कांग्रेस ने 18.82 लाख किसानों का 9270 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ कर दिये थे. जानकारों का मानना है कि कृषि ऋण माफी की अकेली घोषणा ही भाजपा की 15 साल पुरानी सरकार को नापने के लिए काफी साबित हुई थी.

कृषि ऋण के मामले में भूपेश ने एक बार कूटनीति का सहारा लिया. इसके बाद एक अवसर पर उन्होंने कहा था कि किसानों की कर्जमाफी को अगले साल दोहराया नहीं जाएगा. यही कारण था कि भाजपा इस मुद्दे को उठाने से चूक गई और भूपेश बघेल ने प्रथम चरण के मतदान के ठीक 15 दिन पहले इसकी घोषणा कर बाजी मार ली. सोने पर सुहागा यह हो गया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने इस पर सवाल उठाकर भाजपा को पाले के दूसरी तरफ कर दिया. पर क्या खेती किसानी वास्तव में इतने जोखिम का काम है कि किसान को बार-बार

एक बार फिर कर देंगे किसानों का कर्जा माफ

कांग्रेस सरकार आते ही पूर्व की तरह इस बार भी हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे. विधानसभा चुनाव में किसानों का मत निर्णायक है. प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा किसान है और फिर महिलाएं, युवा और व्यवसायी हैं. हमने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों और युवाओं की जेब में पैसा डाला. जब पैसा बाजार पहुंचता है तो व्यापारी भी खुश हो जाते हैं.

● **भूपेश बघेल**
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

कर्जमाफी को चुनावी वादों का हिस्सा न बनाएं

कर्जमाफी से राज्य और केंद्र की अर्थव्यवस्था पर निगेटिव असर होता है. इसका सबसे बड़ा फायदा साठगांठ वालों को मिलता है. इसका फायदा गरीबों की जगह अमीर किसानों को मिलता है. किसानों की कर्ज़ माफी को चुनावी वादों का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए. यह कृषि क्षेत्र में निवेश को रोकता है और संबंधित राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालता है.

● एन रघुरामन

पूर्व गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक (2018)

कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि खुशहाल किसान कर्ज नहीं पटा पाता. तगादों से घबराकर विभिन्न प्रांतों में किसान आत्महत्या करते रहे हैं. देश में कर्जमाफी का एक लंबा इतिहास है. सबसे पहले 1990 में वीपी सिंह सरकार ने देश भर के किसानों का कर्ज माफ कर दिया था. इसके बाद साल 2008-09 के बजट में मनमोहन सिंह सरकार ने पूरे देश में किसानों के करीब 71 हजार करोड़ रुपए माफ करने का फैसला लिया जिसके बाद यूपीए आसानी से सत्ता पर काबिज हो गई थी. इसके बाद कर्जमाफी का वादा राजनीतिक दलों के लिए सत्ता पाने का ब्रह्मास्त्र बन गया. साल 2014 से लेकर अबतक करीब दस राज्य सरकारें किसानों की कर्जमाफी का एलान कर चुकी हैं.

इन राज्यों ने किया किसानों का कर्ज माफ

किसानों का ऋण माफ करने में सबसे पहले आंध्रपदेश ने 24 हज़ार करोड़ रुपए फिर तेलंगाना ने 17 हज़ार करोड़, साल 2016 में तमिलनाडु ने 6 हज़ार करोड़, साल 2017 में महाराष्ट्र ने 34 हज़ार करोड़, वहीं उत्तर प्रदेश ने 36 हज़ार करोड़ और पंजाब ने 1 हज़ार करोड़ रुपए की कर्जमाफी का एलान किया था. हाल की चुनी सरकारों की बात करें तो ये आकड़ा मध्य प्रदेश में 35 से 38 हजार करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ 6 हजार करोड़, और राजस्थान 18 हजार करोड़ रुपए हो सकता है. इस तरह देखें तो साल 2014 से अब तक राज्य सरकारों पर करीब 2 लाख 44 हजार करोड़ का अतरिक्त भार पड़ चुका है.

क्या कहते हैं वित्तीय विशेषज्ञ

वित्तीय मामलों के जानकारों का मानना है कि कृषि ऋण देने के तौर तरीकों में बदलाव किये जाने की जरूरत है. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कर्ज की राशि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए ही किया जा रहा है. इससे किसानों पर कर्ज का बोझ कम होगा और वे आसानी से ऋण चुका पाएंगे. अन्यथा वह हमेशा कर्जमाफी की बाट जोहते रहेंगे. विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कर्जमाफी की योजना का लाभ केवल बड़े किसानों को मिलता है. इसका उपयोग उन्नत कृषि को अपनाने, कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए किया जाना चाहिए. पर अधिकांश किसान कृषि ऋण लेकर इसकी तीन चौथाई राशि दीगर मदों में खर्च कर डालते हैं. कृषि की कमाई से इसे लौटाना संभव नहीं होता. इसलिए साल दर साल वह कर्जदार बना रहता है.

स्थायी समाधान की तलाश जारी

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि कर्ज़माफी की जगह किसानों के उपज की खरीद, उसके रख-रखाव के साथ ही कृषि उत्पादों की मार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए. कृषि के लिए जरूरी आधारभूत संरचना के साथ कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए. उत्पादन क्षति, सूखा, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी किसानों की परेशानी के मुख्य कारण हैं. किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए किसानों की इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के उपायों की खोज करनी चाहिए.

ऐसा क्या किया कि फिर कर्जदार हो गए किसान

पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा कर कांग्रेस ने 2018 में सरकार बनाई और पांच सालों तक किसानों का कर्ज बरकरार रखा. आप सोचिए कि, इस किसान विरोधी सरकार ने ऐसा क्या किया कि, किसान फिर से कर्जदार हो गए. 5 साल के विकास पर इन्हें भरोसा नहीं रहा, अब बस घोषणाओं का सहारा बचा है, क्योंकि दाऊ ने सर्वे रिपोर्ट पढ ली है.

● **डॉ रमन सिंह**

पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

नांदगांव में रमन को गिरीश ने घेरा

रमन के खिलाफ कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को उतारा

कांग्रेस को चिटफंड की रकम लौटाने का होगा लाभ

छत्तीसगढ़ियावाद और जातीय समीकरण भी पक्ष में

कांग्रेस ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को राजनांदगांव में ही घेरने की तैयारी कर ली है. राजनांदगांव जिले की चार सीटों में से यह इकलौती सीट है, जिस पर पिछले चुनावों में भाजपा ने जीत दर्ज की थी. 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी करुणा शुक्ला को लगभग 17 हजार मतों से पराजित किया था. जिले की शेष तीनों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी हार गए थे. सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है, कि इस बार यहाँ भाजपा का खाता नहीं खुलेगा.

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

डॉ. रमन सिंह भाजपा के उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो पिछले पांच वर्षों के दौरान लगातार मुखर रहे हैं. विभिन्न मुद्दों पर भूपेश सरकार को घेरने की वो कोशिश भी करते रहे हैं. कोयला, गोबर, शराब आदि में घोटाले के आरोप लगाने को लेकर भी वे आगे रहे हैं. 2003 में भाजपा की सरकार बनाने वाले वे प्रमुख व्यक्ति थे. उन दिनों वे सांसद थे. इसके बाद डोंगरगांव से उपचुनाव जीतकर वे विधानसभा के सदस्य बने. वे राजनांदगांव से लगातार विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं. वे भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक हैं.

कांग्रेस ने इस बार यहाँ से गिरीश देवांगन को अपना प्रत्याशी बनाया है. तेज तर्रार नेता गिरीश ने प्रत्याशी घोषित होते ही बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है. उन्होंने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है, कि कांग्रेस ने कभी भी हाथ में गंगाजल लेकर शराब बंदी की शपथ नहीं ली. उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और वे उस पर खरा उतरेंगे. भाजपा के नेता झूठ बोलकर कितना भी माहौल बनाने की कोशिश करें, राजनांदगांव की जनता सब जानती और समझती है.

दरअसल, देवांगन के इस दावे के पीछे कुछ ठोस तथ्य हैं. भाजपा के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में चिटफंड घोटाले को लेकर काफी हंगामा हुआ. इसमें पैसा लगाने वाले सर्वाधिक लोग राजनांदगांव से ही थे. इसमें भी सर्वाधिक लोग देवांगन समाज से थे. कांग्रेस की सरकार बनते ही चिटफंड घोटाले पर कार्यवाही शुरू हुई. सरकार ने चिटफंड कंपनी की संपत्ति कुर्क कर यहां 2 करोड़ 46 लाख रुपए निवेशकों के लौटाए. भीतरखाने की खबर है कि इसमें भी सबसे ज्यादा लाभार्थी देवांगन समाज से ही थे. सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला सिद्ध हुआ है.

देवांगन समाज के बारे में कहा जाता है कि ये समूह में फैसला करते हैं. अब ऊँट किस

करवट बैठता है, यह तो मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. सीएम बघेल ने दावा किया है कि भाजपा राजनांदगांव में इस बार खाता नहीं खोल पाएगी यानी एक तरह से चुनाव हारने का दावा कर रही है. वैसे, राजनांदगांव जिले में कुल चार विधानसभा सीटें हैं- इनमें डोंगरगढ़, डोंगरगाँव, खुज्जी और राजनांदगांव शामिल हैं. फिलहाल इनमें से तीन पर कांग्रेस का कब्जा है और केवल एक सीट भाजपा के पास है.

डोंगरगढ़ वह सीट है जहाँ सबसे पहले 7 नवम्बर को मतदान होना है. पिछली बार कांग्रेस के भुनेश्वर शोभाराम बघेल ने 35 हजार से ज्यादा वोटों से यह सीट भाजपा के पूर्व एमएलए विनोद खांडेकर से छीन ली थी. कांग्रेस ने रणनीति में थोड़ा फेरबदल करते हुए इस बार हर्षिता स्वामी बघेल को टिकट दिया है. वे अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व केबिनेट मंत्री डॉ. टुमन लाल की पौत्री हैं. इस सीट पर भाजपा से बागी प्रत्याशी राजेश श्यामकर ने भी निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है, जो भाजपा का गणित बिगाड़ सकता है. खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इसे कांग्रेस का गढ़ माना जा सकता है. पिछले 3 विधानसभा चुनावों से यहां हर बार कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती रही है, तब भी जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी. 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छन्नी चंदू साहू ने भाजपा के हितेन्द्र कुमार साहू को 27,497 वोटों से हरा दिया था. भाजपा ने इस बार चुनाव से लगभग तीन माह पहले ही गीता घासी साहू को यहाँ से प्रत्याशी घोषित कर एक बढ़त ले ली है. गीता साहू राजनांदगांव जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं. उनके पति भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं. लगभग तीन साल पहले सक्रिय राजनीति में आने वाली गीता ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर अपनी जगह पुख्ता कर ली है. कांग्रेस ने उनके खिलाफ भोलाराम साहू को टिकट दिया है. उन्होंने इससे पहले 2013 के चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय प्रत्याशी को पराजित कर विधानसभा प्रवेश किया था. विधानसभा में वे बेहद सक्रिय माने जाते हैं. आंकड़ों की मानें तो वे अन्य विधायकों के औसत 254 प्रश्नों के मुकाबले 420 से अधिक प्रश्न पूछकर अपनी पहचान बना ली थी.

जहाँ तक डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र की बात है तो पिछले चुनाव में यहां से भाजपा के लोकप्रिय विधायक मधुसूदन यादव चुनाव हार गए थे. कुल 189051 वोटरों में से 84581 ने कांग्रेस के दलेश्वर साहू को वोट देकर जिताया था, जबकि यादव को 65498 वोट मिले थे. भाजपा ने यहां से राजनांदगांव के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भरत वर्मा को प्रत्याशी बनाया है.

कांग्रेस ने छीना महिला आरक्षण का मुद्दा

भाजपा के पूर्व मंत्री ने कसा था तंज

कांग्रेस ने उनके खिलाफ उतारी महिला

शैलजा ने सेट किया था 22 का टारगेट

उत्तरी जांगड़े

शेषराज हरबंश

हर्षिता स्वामी बघेल

राजकुमारी मरावी

यशोदा वर्मा

दुलेश्वरी सिदार

अंबिका मरकाम

सावित्री मंडावी

उधेश्वरी पैकरा

गोमती साय

लता उसेण्डी

गीता घासी साहू

» गजेन्द्र

दशकों के इंतजार के बाद सितम्बर में "नारी शक्ति वंदन विधेयक" संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया. हालांकि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा पर फिलहाल इसका असर नवम्बर-दिसम्बर में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी देखा जा रहा है. छत्तीसगढ़ में इस मामले में कांग्रेस ने एक बार फिर बाजी मार ली है. पिछले बार कांग्रेस ने 14 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था जबकि इस बार उसने 18 महिलाओं को मौका दिया है. भाजपा ने पिछली बार 13 महिलाओं को मौका दिया था जबकि इस बार उसने 15 महिला उम्मीदवार खड़े किये हैं.

दरअसल, छत्तीसगढ़ प्रदेश नारी शक्ति वंदन विधेयक या महिला आरक्षण विधेयक के आने से पहले भी महिलाओं को आगे बढ़ाता रहा है, मौजूदा विधानसभा में भी कुल 90 में से 16 विधायक महिला हैं, यह देश की किसी भी

विधानसभा में सर्वाधिक प्रतिशत के लिहाज से एक रिकार्ड है. विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं को टिकट देने में भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही दलों ने उदारता दिखाई है. इस बार 33 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं. कांग्रेस ने इस बार महिलाओं को टिकट देने के लिए कई विधायकों की टिकट काटी है, पिछले चुनाव में भी कांग्रेस द्वारा चुनी गई महिला प्रत्याशियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था.

कांग्रेस ने कसडोल की विधायक शंकुतला साहू का टिकट काटा है, वहीं सरायपाली, बैंकुंठपुर, महासमुंद व सिहावा में वर्तमान विधायकों की टिकट काटकर महिला नेत्रियों पर भरोसा जताया है. पहली बार महासमुंद व सरायपाली सीट से महिलाओ को अवसर दिया गया है. महासमुंद से विधायक विनोद चंद्राकर का टिकट काटकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष डा रश्मि चंद्राकर व सरायपाली से मौजूदा विधायक किस्मतलाल नंद की जगह चातुरी नंद को उम्मीदवार बनाया

गया है, रश्मि और चातुरी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं. जिला कांग्रेस की अध्यक्ष डॉ रश्मि चिकित्सक हैं, उनके पति और ससुर भी चिकित्सक हैं, वे महासमुन्द जनपद की अध्यक्ष रही हैं. वहीं चातुरी भुकेल स्कूल में व्याख्याता हैं, चातुरी ने चौहान सेना बनाकर सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता से कार्य किया, वे इस संगठन की प्रदेशाध्यक्ष हैं.

कांग्रेस की 18 महिला प्रत्याशियों में बिलासपुर संभाग से पांच प्रत्याशी हैं, वहीं बस्तर संभाग से एक, दुर्ग संभाग से चार, सरगुजा संभाग से दो व रायपुर संभाग से कुल छह महिला प्रत्याशी हैं. भाजपा ने सर्वाधिक महिला प्रत्याशी सरगुजा संभाग से उतारे हैं. भाजपा के 15 महिला महिला प्रत्याशियों में बस्तर संभाग से एक, दुर्ग संभाग से दो, सरगुजा संभाग से सात, बिलासपुर संभाग से दो व रायपुर संभाग से तीन महिला प्रत्याशी हैं. भाजपा ने सरगुजा की महत्वपूर्ण सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया है.

कांग्रेस			भाजपा		
आरक्षण	विधानसभा क्षेत्र	प्रत्याशी का नाम	आरक्षण	विधानसभा क्षेत्र	प्रत्याशी का नाम
SC	(17) सारंगढ़	उत्तरी जांगड़े	SC	--	--
	(38) पामगढ़	शेषराज हरबंश		--	--
	(39) सरायपाली	चातुरी नंद		--	--
	(43) बिलाईगढ़	कविता प्राण लहरे	ST	(1) भरतपुर सोनहत	रेणुका सिंह
	(74) डोंगरगढ़	हर्षिता स्वामी बघेल		(6) प्रतापपुर	शकुंतला सिंह पोर्ते
ST	(06) प्रतापपुर	राजकुमारी मरावी		(8) सामरी	उधेश्वरी पैकरा
	(15) लैलूंगा	विद्यावती सिदार		(14) पत्थलगांव	गोमती साय
	(23) पाली तानाखार	दुलेश्वरी सिदार		(15) लैलूंगा	सुनीति सत्यानंद राठिया
	(56) सिहावा	अंबिका मरकाम		(83) कोण्डागांव	लता उसेंडी
	(60) डौंडीलोहारा	अनिला भेड़िया	GEN	(5) भटगांव	लक्ष्मी राजवाड़े
	(80) भानुप्रतापपुर	सावित्री मंडावी		(12) जशपुर	रायमुनि भगत
GEN	(3) बैकुंठपुर	अंबिका सिंहदेव		(17) सारंगगढ़	शिवकुमारी चौहान
	(28) तखतपुर	डॉ. रश्मि आशीष सिंह		(36) चंद्रपुर	बहुरानी संयोगिता
	(42) महासमुंद	डॉ. रश्मि चन्द्राकर		(39) सरायपाली	सरला कोसरिया
	(47) धरसींवा	छाया वर्मा		(41) खल्लारी	अलका चन्द्राकर
	(57) कुरूद	तारिणी चन्द्राकर		(58) धमतरी	रंजना दीपेन्द्र साहू
	(59) संजारी बालोद	संगीता सिन्हा		(71) पंडरिया	भावना बोहरा
	(73) खैरागढ़	यशोदा वर्मा		(77) खुज्जी	गीता घासी साहू

इस बार कुरुद की तारणहार होगी तारिणी

भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अजय चन्द्राकर को कांग्रेस ने इस बार उनके निर्वाचन क्षेत्र कुरुद में ही घेरने की तैयारी की है. चार बार के विधायक अजय चंद्राकर भाजपा आरोप पत्र समिति के भी संयोजक हैं और एक मुखर नेता के रूप में जाने जाते हैं. भ्रष्टाचार और महिला आरक्षण को लेकर भी वे कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं. पिछले चुनाव में जब भाजपा के अधिकांश विकेट गिर गए थे, अजय तब भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे. कांग्रेस ने इस बार उनके खिलाफ तारिणी नीलम चंद्राकर को प्रत्याशी बनाया है. तारिणी जिला पंचायत सदस्य होने के साथ ही स्थानीय महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति की भी अध्यक्ष हैं.

महिला मामले में टिप्पणी पड़ सकती है भारी

पिछले चुनाव में हुआ था 89 प्रतिशत मतदान

कांग्रेस ने निर्दलीय की पत्नी को बनाया प्रत्याशी

» पी. मोहन

कुरुद विधानसभा क्षेत्र धमतरी जिले की तीन सीटों में सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण है. यह भाजपा के पूर्व केबिनेट मंत्री एवं कद्दावर नेता अजय चन्द्राकर का निर्वाचन क्षेत्र है. 2008 के निर्वाचन को छोड़कर 1998 से अब तक वे लगातार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. 2008 में इस सीट पर कांग्रेस के लेखराम साहू की जीत हुई थी. तब इस सीट पर पांच-पांच लेखराम साहू एक साथ चुनाव लड़ रहे थे. चारों हमनामों ने मिलकर इस चुनाव में कुल 6999 वोट काटे थे. इन्हें क्रमशः 3995, 1791, 757 और 456 वोटों से संतोष करना पड़ा था.

अजय चन्द्राकर

स्कूली जीवन से ही मुखर रहे अजय चंद्राकर केबिनेट मंत्री, संसदीय सचिव, भाजपा विधायक दल के सचेतक, पार्टी प्रवक्ता और कार्यसमिति सदस्य रहे हैं. फिलहाल वे प्रदेश भाजपा आरोप पत्र समिति के संयोजक हैं. 1998, 2003, 2013 और 2018 में वे यहां से चुनाव जीत चुके हैं. पर इस बार उनकी राह आसान नहीं होगी. कांग्रेस ने उनके खिलाफ महिला प्रत्याशी उतारा है. तारिणी के पति नीलम चंद्राकर ने पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और अजय चंद्राकर को कड़ी चुनौती दी थी. अजय चंद्राकर को 72 हजार और नीलम चंद्राकर को 60 हजार से ज्यादा मत प्राप्त हुए थे. कांग्रेस यहां महज 15 प्रतिशत वोटों के साथ हाशिए पर आ गई थी.

इन मुद्दों पर घिर सकते हैं अजय

महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान अजय चन्द्राकर ने कहा था कि महिलाओं का कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में वर्चस्व रहा है, बावजूद इसके वह महिला आरक्षण विधेयक नहीं ला पाई. उन्होंने इंदिरा, सोनिया और प्रियंका का नाम लेते हुए यह बातें कही थीं. भाजपा विधायक ने कहा था कि कांग्रेस को शुरू से ही महिलाएं चलाती आ रही हैं. पहले इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी और अब प्रियंका गांधी. इस पार्टी में महिलाएं शुरू से फोकस में हैं. यदि वे महिलाओं को लेकर गंभीर होते तो 10 साल के शासनकाल में महिला आरक्षण बिल ले आते.

तारिणी चन्द्राकर

पिछले चुनाव से पहले 2017 में अजय चंद्राकर के खिलाफ ईडी ने अनुपातहीन संपत्ति का मामला शुरू किया था. कुरुद के ही आरटीआई एक्टिविस्ट कृष्ण कुमार साहू एवं रायपुर के डॉ मंजीत कौर बल ने उनके खिलाफ पहले उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी. तकनीकी आधार पर इसे खारिज कर दिया गया था. बाद में दोनों ने 9 हजार पृष्ठों के दस्तावेज पीएमओ को भेजे थे. इसपर पीएमओ ने राज्य सचिवालय को पत्र लिखा था जिसकी सीएम डॉ रमन सिंह ने तसदीक की थी. ईडी ने इस मामले में एक दर्जन से ज्यादा बैंकों से मंत्री के खातों में मौजूद रकम और निवेशों की जानकारी मांगी थी. इन दस्तावेजों में मंत्री अजय चंद्राकर की रायपुर, धमतरी, कुरुद, महासमुंद सहित राज्य

के कई इलाकों में नामी बेनामी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया गया था. उस समय चंद्राकर के पास ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा कई मलाईदार विभागों का प्रभार था. आरोप था कि मंत्री के परिजन इन विभागों में ठेकेदारी का काम कर रहे थे. इन विभागों में भ्रष्टाचार के कई मामले ईओडब्लू और एंटी करप्शन ब्यूरो में विचाराधीन थे.

तारिणी के पास सक्रियता की थाती

भाजपा के कद्दावर नेता के मुकाबले उतारी गई तारिणी चन्द्राकर कमोबेश एक स्थानीय तौर पर सक्रिय नेता हैं. बतौर जिला पंचायत सदस्य उनकी अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी पैठ है. महिला उत्थान, सशक्तिकरण एवं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में वे अग्रणी रही हैं. सामाजिक कार्यक्रमों में भी उनकी बढ़-चढ़कर भागीदारी रहती है. इसके अलावा वे कुरुद महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति की भी अध्यक्ष हैं. विद्यार्थियों के बीच भी निरंतर सक्रिय रहते हुए वे उनकी समस्याओं को कम करने की कोशिश करती हैं. गत वर्ष उन्हें नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया था. उनके पति नीलम चंद्राकर ने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस को पीछे धकेल दिया था. इसका लाभ भी तारिणी को मिलेगा.

धमतरी के तीनों निर्वाचन क्षेत्र में जाति न्यूट्रलाइज

कुरुद निर्वाचन क्षेत्र धमतरी जिले के अन्तर्गत आता है. यहां विधानसभा की तीन सीटें हैं. तीनों सीटों धमतरी, कुरुद और सिहावा में जातिगत समीकरणों को इस बार न्यूट्रलाइज कर दिया गया है. कुरुद में अजय चंद्राकर की टक्कर तारिणी नीलम चंद्राकर से है. धमतरी में रंजना साहू का ओंकार साहू से तो सिहावा में अंबिका मरकाम की टक्कर श्रवण मरकाम से है. कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में हो रहे प्रयोग राष्ट्रीय स्तर जारी बहस को नई दिशा देने में सफल होंगे.

खूबचंद बघेल का निर्वाचन क्षेत्र फिर सुर्खियों में

फिल्म स्टार के उतरने से हाई प्रोफाइल हुआ धरसीवां

भाजपा के अनुज को टक्कर देंगी कांग्रेस की छाया

स्वामी आत्मानंद का गांव भी इसी विस क्षेत्र में

धरसीवां विधानसभा सीट एक बार फिर हाई प्रोफाइल हो गया है. भाजपा ने यहां से पद्मश्री अनुज शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है. रामानुज शर्मा उर्फ अनुज शर्मा, पद्मश्री राधेश्याम बारले और पूर्व आईएएस राजपाल सिंह त्यागी ने कुछ ही समय पहले भाजपा में प्रवेश किया था. छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार माने जाने वाले चाकलेटी हीरो अनुज शर्मा के लिए चुनाव लड़ने का यह पहला मौका है. कांग्रेस ने इस सीट पर राज्यसभा के पूर्व सदस्य छाया वर्मा को उतारा है. छाया वर्मा 2016 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई थीं. वैसे इस सीट पर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने भी अमित बघेल को अपना प्रत्याशी उतारा है.

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

धरसीवां विधानसभा सीट की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ आंदोलन के प्रणेता डॉ खूबचंद बघेल का निर्वाचन क्षेत्र रहा है. 1952 में डॉ बघेल ने जब पहली बार यहां से चुनाव जीता था तो यह पचेड़ा विधानसभा क्षेत्र कहलाता था. 1957 को पचेड़ा विधानसभा धरसींवा विधानसभा में तब्दील हो गया. डॉ. खूबचंद बघेल एक बार फिर इसी सीट से निर्वाचित होकर विधायक बने थे. कुर्मी बहुल क्षेत्र होने की वजह से यहां ज्यादातर कुर्मी विधायक ही चुने जाते रहे हैं. 1957 के बाद डॉ. हरिप्रेम बघेल, दौलतराम वर्मा, बालाराम वर्मा (भाजपा) व देवजी भाई पटेल भी

तीन बार इस सीट से निर्वाचित हो चुके हैं. स्वामी आत्मानंद का गांव बरबंदा भी इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

धरसीवां विधानसभा क्षेत्र से पिछले चुनाव में कांग्रेस की अनीता योगेन्द्र शर्मा ने भाजपा के देवजी भाई पटेल को लगभग 20 हजार मतों से पराजित किया था. इस सीट पर उस समय कुल 16 प्रत्याशी मैदान में थे जिनमें से 3 को छोड़कर कोई भी चार अंकों तक नहीं पहुंच पाया था. इससे पहले 2013 में देवजीभाई पटेल ने अनीता योगेन्द्र शर्मा को पराजित कर दिया था. 2008 में भी देवजी भाई पटेल कांग्रेस के छत्रपाल सिरमौर को पराजित कर विधानसभा पहुंचे थे. 2003 में कांग्रेस ने यहां से छाया वर्मा को प्रत्याशी बनाया था. भाजपा के देवजी भाई पटेल छाया को पराजित कर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे. कुर्मी बहुल क्षेत्र होने के कारण कांग्रेस हमेशा यहां से कुर्मी प्रत्याशी देने का प्रयास करती है.

भाजपा प्रत्याशी का हो रहा विरोध

भाजपा ने इस बार रायपुर निवासी फिल्म कलाकार अनुज शर्मा को यहां से प्रत्याशी बनाया है. उसे पैराशूट प्रत्याशी बताया जा रहा है. इसे लेकर स्थानीय भाजपा में काफी आक्रोश है. पार्टी के डेढ़ दर्जन दिग्गज कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं. इस सीट से भाजपा के तीन बार के विधायक रहे देवजी भाई पटेल ने भी क्षेत्र में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने नामांकन फार्म भी खरीद लिया है. क्षेत्र के राकेश यादव, महेश नायक, राबिन साहू जैसे कर्मठ नेताओं ने भी अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दिया है. कार्यकर्ताओं को डर है कि यदि बाहरी प्रत्याशी जीत गया तो उनकी पूछपरख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी.

नया नहीं है छाया का चेहरा

छाया वर्मा के पति डॉ. डी. आर. वर्मा उपस्वास्थ्य केंद्र मांढर में मुख्य चिकित्सक रहे हैं. 1999 में छाया इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य चुनी गई. इसके बाद वह रायपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी बनी. 2003 में उसने कांग्रेस की टिकट पर धरसींवा से चुनाव भी लड़ा. छाया वर्मा क्षेत्र की कई महिला मंडली और संगठनों से वर्षों से जुड़ी हुई हैं.

धरसीवा से कांग्रेस ने तीसरी बार महिला प्रत्याशी को उतारा है. इससे पहले पिछले चुनाव में अनीता शर्मा यहां से विधायक चुनी गई थीं. इस सीट पर वे पहली महिला विधायक निर्वाचित हुई थीं.

प्रदूषण है सबसे बड़ा मुद्दा

धरसींवा ब्लॉक में बड़ी संख्या में उद्योग होने के कारण यहां प्रदूषण काफी है. पिछले 25 वर्षों से इसका असर लोगों के स्वास्थ्य के साथ ही फसलों पर भी देखा जा रहा है. औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद क्षेत्र में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है. रेलवे यहां की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है. क्षेत्र में सिलयारी और मांढर दो रेलवे स्टेशन है. इसका लाभ 30 से अधिक गांव के लोगों को मिल रहा था. कोरोनाकाल के बाद से लगभग दर्जनभर लोकल ट्रेनें बंद हैं, जिसके कारण शहरों में नौकरी करने वाले कई लोगों की नौकरी छूट गई. लोकल ट्रेनों की संख्या कम होने के साथ ही किराया तीन गुना बढ़ा दिया गया है. इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है.

किसान कांग्रेस के साथ

क्षेत्र में ज्यादातर वोटर किसान है. जो कर्जमाफी और 20 क्विंटल धान ₹2800 में बेचने का लाभ उठाना चाहती है. 20 क्विंटल धान बेचने के लिए किसानों ने खेतों में जी तोड़ मेहनत की है. कुरुद-सिलयारी के किसान विनय नायक व हिमांशु वर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष तक हमारे गांव में खेती का रकबा 2600 एकड़ था जो इस वर्ष बढ़कर 3200 एकड़ हो गया. धान की फसल इतनी अच्छी है कि किसान 20 क्विंटल से भी ज्यादा उत्पादन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं. भाजपा शासनकाल में किसान अपने खेतों को 15 लाख रुपए एकड़ में बेचने को विवश हो गए थे. अब स्थिति बदल गई है. जमीन बेचना तो दूर अब किसान जमीन खरीदने की बात करने लगे हैं. जमीन बेच चुके किसान अब ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं.

भाजपा में शामिल होते ही धुल जाते हैं दाग!

भाजपा के शीर्ष नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भ्रष्टाचारियों को उलटा लटकाकर सीधा करने का दावा करते रहे हैं. पर उनका यह दावा खोखला है. स्वयं उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, राज्यसभा सदस्य बनाती रही है. कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होते ही ऐसे नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के दाग पूरी तरह से धुल जाते हैं. ऐसे लोग पार्टी के स्टार प्रचारक भी बन जाते हैं. मजे की बात यह है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं के खिलाफ भाजपा या उसका शीर्ष नेतृत्व अमूमन खामोश ही रहता आया है.

भ्रष्टों को सीएम, मिनिस्टर भी बनाती रही है भाजपा

भूपेश सरकार की योजनाओं के कायल हैं मोदी भी

रमन सरकार के घोटालों पर क्यों खामोश है भाजपा

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

दरअसल, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं प्रशंसक रहे हैं. समय-समय पर उन्होंने सीएम भूपेश की पीठ भी थपथपाई है. छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार इन अभिनव योजनाओं के कारण मिल चुके हैं. इसलिए विधानसभा चुनाव में वह केवल घोटालों का उल्लेख करती है, न कोई आंकड़े देती है और न ही कोई सबूत दे पाती है.

घोटालों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं

छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया है. उसने सरकार पर घोटाले करने, धर्मांतरण को बढ़ावा देने और केन्द्रीय योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचने देने का आरोप लगाया है. पर ताज्जुब की बात यह है कि इनमें से एक भी मुद्दे को लेकर भाजपा ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया. घोटाले के उसके आरोप पर सारी मेहनत ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी केन्द्रीय एजेंसियां ही करती रहीं. छापेमारी की, कुछ अफसरों और कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया पर कार्रवाई वहीं रुकी हुई है.

भ्रष्टाचार के इन आरोपों की जांच तक नहीं

कांग्रेस ने भी समय समय पर नान घोटाला, प्रियदर्शिनी बैंक घोटाला, पनामा पेपर लीक, हेलीकॉप्टर खरीदी घोटाला का मामला उठाया. पर इनमें से किसी भी मामले की कभी जांच नहीं हुई. केन्द्रीय स्तर के किसी भी नेता ने कभी इस मामले में कोई बात तक नहीं की. चिटफंड घोटाले पर तो राज्य सरकार ने कार्रवाई भी की और लोगों के पैसे लौटाने शुरू किये पर केन्द्रीय एजेंसियां इस मामले में भी मौन

ही बनी रही. भ्रष्टाचारियों को उलटा लटकाने वाले भी इसकी तरफ से आंखें मूंदे रहे.

भाजपा में जाते ही इन भ्रष्टाचारियों के दाग धुले

कांग्रेस की तरूण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हिमंत बिस्वा सरमा शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी था. भाजपा में जाते ही उनके खिलाफ जांच बंद हो गई और आज वे मुख्यमंत्री हैं. इसी घोटाले में ममता बनर्जी सरकार के कद्दावर मंत्री शुभेंदु अधिकारी भी आरोपित थे. उन पर नारदा स्टिंग आपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा. शुभेन्दु अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता हैं. आसनसोल के जितेन्द्र तिवारी पर कोयला चोरी और तस्करी के आरोप थे पर भाजपा में जाते ही उनके खिलाफ जांच बंद हो गई. महाराष्ट्र के नारायण राणे पर भी मनी लॉन्डरिंग का आरोप था. 2019 में भाजपा में शामिल होते ही उन्हें केन्द्रीय मंत्री बना दिया गया. कर्नाटक में बीएस येदुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार के आरोप थे. लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था. 2016 में उनकी भाजपा में घर वापसी हुई और फिर उन्हें क्लीन चिट मिल गया. महाराष्ट्र के प्रवीण डारेकर, गुजरात के हार्दिक पटेल, महाराष्ट्र के अजित पवार, पश्चिम बंगाल के मुकुल रॉय भी ऐसे ही नेता हैं जिन्हें भाजपा की शरण लेते ही भ्रष्टाचार, राष्ट्रद्रोह, मनी लॉन्डरिंग जैसे आरोपों से मुक्ति मिल गई.

दो माह पहले प्रत्याशी उतारने का यह था गणित!

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति काफी कुछ कहती है. भाजपा ने यहां दो माह पहले ही अपने 30 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी. इससे संदेश गया था कि भाजपा इस बार पूरी तैयारी में है और उसका आत्मविश्वास सिर चढ़ कर बोल रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह भी भाजपा की रणनीति का हिस्सा था. अब वह उन प्रत्याशियों को फायनेंस कर रही है जो कांग्रेस प्रत्याशियों के टिकट काट सकते हैं. वैसे भी अजीत जोगी द्वारा स्थापित जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) के बारे में कहा जाता रहा है कि वह भाजपा की बी-पार्टी है. जब तक जोगी जीवित रहे भाजपा एकतरफा जीतती रही. ऐसी ही अटकलें हाल ही में लांच हुई जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के लिए भी लगाई जा रही हैं. कांग्रेस के समान मुद्दों वाली इस पार्टी के कुछ प्रत्याशियों ने हालांकि पार्टी के गठन के समय ही अपने निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी थी पर अब इनकी भी प्रतिदिन लिस्ट आ रही है. धरसीवां में कांग्रेस प्रत्याशी छाया वर्मा और भाजपा प्रत्याशी अनुज शर्मा के बीच जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अमित बघेल, पाटन में जहां सीएम भूपेश बघेल और भाजपा के सांसद विजय बघेल आमने सामने हैं वहां साहू वोट काटने के लिए जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से मधुकांत साहू मैदान में हैं. इसी तरह दुर्ग ग्रामीण सीट पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने भी जेसीपी के कामेश साहू मैदान में हैं. राजनांदगांव में भाजपा के डॉ रमन सिंह और कांग्रेस के गिरीश देवांगन के बीच भी जेसीपी के मनीष देवांगन खड़े हैं.

कहीं इसलिए तो नहीं खटक रही भूपेश सरकार?

भूपेश बघेल सरकार के रहते अदानी को छत्तीसगढ़ की खदानों पर एकछत्र राज करने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है. हसदेव के जंगलों की अंधाधुंध कटाई के मामले में अदानी को आदिवासियों के साथ ही भूपेश बघेल के विरोध का भी सामना करना पड़ा. बस्तर की नंदराज पहाड़ी सहित 13 खदानों के मामले में भी अदानी ग्रुप को निरस्तीकरण सहित काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. छत्तीसगढ़ में अदानी के खिलाफ जबरदस्त माहौल है. संभवतः केन्द्र को इसीलिए भूपेश सरकार चुभ रही है.

कर्जमाफी को लेकर दोगली नीति

भाजपा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर रेवड़ियां बांटकर सत्ता में आने के आरोप लगाती है. वह किसानों का कर्ज माफ किये जाने को लेकर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर हमलावर है. कांग्रेस का कहना है कि केन्द्र सरकार बड़े लोगों का करोड़ों रुपए का कर्जा राइट ऑफ कर देती है और किसानों की कर्ज माफी पर उंगली उठाती है.

रमन परिवार से तीन को टिकट

डॉ. रमन सिंह, राजनांदगांव

विक्रांत सिंह, खैरागढ़

भावना बोहरा, पंडरिया

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के निकट आते ही सियासी सरगरमी बढ़ती जा रही है. कांग्रेस जहाँ दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रही है, वहीं भाजपा भी परिवर्तन का नारा देकर पांच साल बाद फिर राज सिंहासन में वापसी की बात कर रही है. लेकिन जमीनी सच्चाई यह है, कि दोनों ही टिकट वितरण से उपजे असंतोष के चलते भीतरघात से जूझ रहे हैं. अपनी जीत को लेकर पांच साल सत्ता में रही अति उत्साहित कांग्रेस ने तो बहुत हद तक असंतुष्टों को एडजस्ट करने का भरोसा दिलाकर साधने की कोशिश की है, लेकिन भाजपा में टिकट आक्रोश ने पार्टी का संकट बढ़ा दिया है. अधिकतर पुराने चेहरों पर दांव खेलने की रणनीति से पार्टी की स्थिति **बहुत कठिन है डगर पनघट की..** जैसी हो गई है. टिकट चयन में भाजपा की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के रणनीतिकारों पर भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के हावी होने की कीमत पार्टी को फिर पाँच साल इंतजार के रूप में चुकानी पड़ सकती है.

» छ.ग. आजतक ब्यूरो

राज्य में चुनावी घमासान के बीच टिकट को लेकर भाजपा की रणनीतिक अदूरदर्शिता ने पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं. इससे जीत के बारे में आरएसएस कैंप में आशंका और निराशा व्याप्त है. आरएसएस के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार भाजपा ने अपनी घोषणा के विपरीत फिर से अधिकतर उन्हीं घिस-पिटे चेहरों को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिससे जमीनी कार्यकर्ताओं में हताशा और नाराजगी है. जो लोग 2018 के चुनाव में अपनी धूमिल छवि और सत्ताविरोधी लहर के कारण पराजित हुए थे, उन्हें दोबारा टिकट दे देने से संघ और जमीनी कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी की जीत बहुत मुश्किल प्रतीत हो रही है. इससे कांग्रेस हलकों में उत्साह का माहौल है. चुनाव की घोषणा के पूर्व भाजपा

परिवारवाद और वंशवाद के आरोप खोखले साबित

घिसे पिटे चेहरों से उकताई जनता, कार्यकर्ता निराश

नाले में बह गई आरएसएस स्वयंसेवकों की मेहनत

कपूर की तरह उड़ गया – इस बार 70 पार का ख्वाब

के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से आरएसएस व अपने खुफिया सर्वे के बाद अच्छी छवि वालों को ही विनिंग केंडिडेट बनाने की घोषणा की थी, उससे जमीनी कार्यकर्ताओं में उत्साह था. भाजपा हाईकमान ने सभी सीटों पर विनिंग केंडिडेट का पता लगाने दो आरएसएस नेताओं से सर्वे कराया था. इसके बाद जब पार्टी ने चुनाव घोषित होने के दो माह पूर्व तीस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, तो लगा कि आगे भी पार्टी इसी तरह के बेदाग लोगों को चुनाव मैदान में उतारेगी. प्रत्याशियों के चयन से भाजपा ने अपनी राजनीतिक सजगता और वृहद तैयारी का संदेश दिया था. लेकिन इसके बाद एक एक कर तीन चरणों में प्रत्याशियों की घोषणा से यह उत्साह निराशा और असंतोष में बदल गया है. टिकट वितरण में घोटालों को लेकर कांग्रेस के लगातार निशाने पर रहे तीन बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह की चली है. दूसरी सूची में जिन 55 लोगों को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, उनमें अधिकांश लगातार चुनाव

परिवारवाद पर लाजवाब

कांग्रेस और राहुल गाँधी पर परिवारवाद का राग अलापने वाली भाजपा लगातार केंद्र व राज्यों में परिवार को पोस रही है. केंद्र सरकार और राज्यों में उसके कई नेताओं के पुत्र और परिजन चुनाव जीतने के बाद सत्तासुख भोग रहे हैं. अब छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम तथा राजनांदगांव से प्रत्याशी डॉ. रमन सिह ताजा उदाहरण हैं. विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में न सिर्फ उनके अधिकतर लोगों को टिकट दी गई है बल्कि खुद उनके परिवार से तीन सदस्यों को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है. उनके अलावा रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह को खैरागढ़ से टिकट दी गई है. राजनीतिक शुचिता की दुहाई देने वाली पार्टी यहीं नहीं रूकी बल्कि अपने चहेते रमन सिंह की भांजी भावना वोहरा को भी पंडरिया से उम्मीदवार बनाया है. एक ओर तो भाजपा ने अपने पंद्रहवर्षीय सरकार में घपले और घोटालों से घिरे रमन सिंह को सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया, वहीं दूसरी ओर उनके तीन चौथाई लोगों को ही टिकट नहीं दिया बल्कि खुद उनके परिवार से तीन-तीन लोगों को प्रत्याशी बनाया है. इससे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है. उनके तीन चौथाई चहेतों को टिकट देने से जनता में यह संदेश गया है, कि चुनाव जीतने की स्थिति में रमन सिंह ही सीएम बनेंगे. पार्टी कार्यकर्ताओं में यह चर्चा है कि पार्टी की मनमानी का चरमपंथ देखिए कि जहाँ वर्षों से आम कार्यकर्ता झंडा, दरी व बड़े नेताओं को माला पहनाते - पहनाते अपनी उम्मीदवारी का इंतजार कर रहे हैं वहीं हमारी ऐसी पार्टी अपने नेता के परिवार के तीन सदस्यों को टिकट दे रही है, जो खुद दूसरे दलों को दिन-रात पानी पी-पी कर परिवारवाद के लिए कोसते रहती है.

लड़ते रहे हैं और पराजित भी हुए हैं. इन घिसे पिटे चेहरों से जनता व कार्यकर्ता दोनों ही उकता चुके हैं. पार्टी ने सीएम के रुप में किसी भी नेता का चेहरा सामने न रखकर मोदी मैजिक पर चुनाव लड़ने की रणनीति अख्तियार की. लेकिन टिकट देने में जिस हिसाब से डॉ. रमन सिंह के लोगों को अधिक महत्व दिया, उससे भाजपा की कथनी और करनी में फर्क साफ दिखाई देता है. दूसरी सूची को देखकर कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा हुई है. सूची में टिकटार्थियों के रूप में उन्हीं लोगों के नाम हैं, जिनके खिलाफ जनता और कार्यकर्ता दोनों में ही नाराजगी है. टिकट चयन में पिछले चुनाव में हार की मुख्य वजह बने रमन सिंह के सामने आरएसएस की भी नहीं चली है. वहीं आरएसएस बैकग्राउंड के भी जिन लोगों को टिकट दी गई है, उनकी जमीनी पकड़ बहुत कमजोर बताई जा रही है. छत्तीसगढ़ के पूर्व सरकार्यवाह बिसराराम यादव के पुत्र गजेंद्र यादव को दुर्ग शहर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है जो क्षेत्र के लिए नया चेहरा है. इसी तरह पार्टी ने अपने कथित सिद्धांत व घोषणा के उलट कई ऐसे दागियों को उम्मीदवार बनाकर सीधे-साधे और वरिष्ठ भाजपाइयों की भी नाराजगी में मोल ले ली है. बताते हैं कि कई युवा प्रत्याशी हैं, जिन्हें नशे की लत है और कुछ की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है. कुल मिलाकर राज्य की अधिकतर सीटों पर कमजोर, दागी और पार्टी की विचारधारा से अलग लोगों को प्रत्याशी बनाए जाने से भाजपा का पचहत्तर प्लस सीट जीतने का दावा खोखला साबित होता नज़र आ रहा है. पंद्रह वर्ष तक सत्तासीन रहने के बाद पाँच साल सत्ता से विमुख रहने का दर्द झेल रही भाजपा यदि अपने लंबे अनुभव और मातृ संस्था आरएएसएस के सर्वे के अनुरूप टिकट चयन करती तो चुनाव जीतने की संभावना मजबूत होती, लेकिन उसने तीन बार के सीएम रमन सिंह और उनके लोगों का दबाव मोल लेकर खुद अपनी मुसीबतें बढ़ा ली हैं.

युवा मितान परिवहन योजना

काफी नहीं है कॉलेज तक की सुविधा

» दीपक रंजन दास

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए युवा मितान परिवहन योजना को हरी झंडी दे दी है. योजना के तहत विद्यार्थी अब अपने घर से कालेज तक बसों में मुफ्त आना-जाना कर सकेंगे. इस योजना पर लगभग 110 करोड़ रुपए खर्च होने का पूर्वानुमान है. इसका आधा खर्च सरकार उठाएगी जबकि आधा भार बस संचालक वहन करेगा. उम्मीद जताई जा रही है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की कॉलेज में आमद बढ़ेगी जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में इजाफा होगा. पर यह पूरी तस्वीर नहीं है. इस योजना का लाभ विद्यार्थी एमओयू पार्टनर कालेजों तक जाने के लिए नहीं उठा सकेंगे.

युवा मितान परिवहन योजना को कांग्रेस ने 2018 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था. योजना को प्रारंभ कर सरकार ने अपना एक और वायदा पूरा कर दिया है. इस योजना का लाभ लगभग एक लाख विद्यार्थी उठा पाएंगे. विद्यार्थियों को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए ऐप बना दिया गया है. विद्यार्थी को ऐप पर कॉलेज और अपने निवास स्थान के अलावा अपनी अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो और दसवीं की अंकसूची अपलोड करना होगा. इसके बाद कालेज इस आवेदन का अनुमोदन करेगा. इसके बाद विद्यार्थी का ई-बस पास जनरेट हो जाएगा जिसे डाउनलोड और प्रिंट कर विद्यार्थी को अपने पास रखना होगा. बस संचालक विद्यार्थी के ई-बस पास को स्कैन कर डाया इकट्ठा करेगा. इस डाटा के आधार पर वह कॉलेज से भुगतान प्राप्त कर सकेगा. यह भुगतान वास्तविक किराये के आधा होगा.

इस योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रतिदिन महाविद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना है. वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी या तो साइकिल का उपयोग करते हैं या फिर बसों से ही कॉलेज तक आना जाना करते हैं. पर किराया ज्यादा होने के कारण वे सप्ताह में दो तीन दिन या परीक्षाओं वाले दिन ही कालेज आ पाते

छात्राओं को होगा सर्वाधिक लाभ

वर्ष 2018-19 में जहां 91,982 छात्रों की तुलना में 1,34,391 छात्राओं ने कालेज में एडमिशन लिया वहीं 2022-23 में 1,28,310 छात्र और 2,06,829 छात्राओं ने महाविद्यालयों में दाखिला लिया. छात्राओं की संख्या छात्रों के मुकाबले 61 प्रतिशत अधिक है. बड़ी संख्या में छात्राएं आवागमन की असुविधा और खर्च के कारण कालेज नहीं आ पातीं. अब उनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी.

हैं. ऐसे विद्यार्थियों की एक बड़ी मुश्किल अब आसान हो जाएगी. वे प्रतिदिन समूह में कालेज आ सकेंगे. इससे कॉलेज कैम्पस भी प्राणवंत होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की जद्दोजहद

पिछले चार सालों में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) ने राज्य के 192 महाविद्यालयों का मूल्यांकन किया है. इससे पहले साल 2003 से 2018 के बीच केवल 36 महाविद्यालयों की नैक ग्रेडिंग करवाई जा सकी थी. यूजीसी ने ट्वीट करके बताया था कि नैक ग्रेडिंग करवाने के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल स्थान पर है. एजुकेशन वर्ल्ड ऑटोनॉमस कॉलेज रैंकिंग 2023-24 में छत्तीसगढ़ के 6 कॉलेजों को टॉप 100 में जगह मिली है. शासकीय वीवायटी महाविद्यालय दुर्ग को 9वां स्थान मिला है. वहीं बिलासपुर के बिलासा कन्या महाविद्यालय को 14वां, राघवेन्द्र राव विज्ञान महाविद्यालय को 19वां, दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव को 34वां, राजीव गांधी कालेज अंबिकापुर को 42वां, नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय रायपुर को 54वां रैंक प्राप्त हुआ है. छत्तीसगढ़ के "प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन" को देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है.

युवा मतदाताओं को रिझाने की कोशिश!

छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों में 18 वर्ष से 22 वर्ष की आयु के कम से कम 18.68 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले द्वारा जारी अंतिम संशोधित मतदाता सूची के अनुसार, राज्य में कुल मतदाता 2.03 करोड़ हैं. इनमें 1.01 करोड़ पुरुष वोटर्स तो 1.02 करोड़ महिला वोटर्स हैं. दिव्यांग वोटर्स की संख्या 1.6 लाख है. इसके अलावा मतदाता सूची में 1.86 लाख वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक) और 19,839 सेवा मतदाता भी हैं. युवा मितान परिवहन योजना के माध्यम से सरकार ने इन नए वोटरों को रिझाने की कोशिश भी की है.

48 फीसदी बढ़ गए विद्यार्थी

छत्तीसगढ़ में 285 शासकीय महाविद्यालय, 12 अनुदान प्राप्त आशासकीय महाविद्यालय एवं 252 अनुदान अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं. कन्या महाविद्यालयों की संख्या 26 है. 2018-19 में महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 लाख 26 हजार 373 थी जो 2022-23 में 48 प्रतिशत बढ़कर 3 लाख 35 हजार 139 हो गई. विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भूपेश सरकार ने चार साल में 33 नवीन शासकीय महाविद्यालय खोल दिए. इस अवधि में 76 अशासकीय महाविद्यालय भी प्रारंभ हुए. सरकार ने 15 और नए कालेजों की हाल ही में घोषणा की है.

क्या है एक्सटेंडेड कैम्पस?

शासकीय नवीन महाविद्यालयों में अभी सुविधाएं पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई हैं. अनुभवी प्राध्यापकों की तो कमी है ही, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों का भी अभाव है. इससे निजात पाने के लिए अधिकांश महाविद्यालयों ने शहरी निजी एवं शासकीय महाविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं. एमओयू का आशय नवीन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को सर्वसुविधायुक्त महाविद्यालयों में प्रायोगिक कक्षाओं का लाभ प्रदान करना है. इसलिए एमओयू पार्टनर कॉलेज को भी मूल कॉलेज का एक्सटेंडेड कैम्पस मानना चाहिए. पर मुफ्त बस सुविधा फिलहाल विद्यार्थियों को केवल अपने मूल कॉलेज तक ही मिलेगी. इससे वे एमओयू पार्टनर कॉलेज तक नहीं पहुंच पाएंगे.

गुणवत्ता बढ़ाने हर संभव उपाय होंगे

युवा मितान परिवहन योजना अभी अपने प्रारंभिक चरण में है. ऐप लांच कर दिया गया है. विद्यार्थी अपना पंजीयन करा रहे हैं. महाविद्यालय बस पास का अनुमोदन करेंगे. कालेजों में उपस्थिति बढ़ने का लाभ विद्यार्थियों के साथ ही महाविद्यालयों को भी होगा. सरकार संवेदनशील है तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने अनेक उपाय कर रही है. एमओयू पार्टनर कालेजों तथे ग्रंथागारों तक विद्यार्थियों की पहुंच भी सुनिश्चित होनी चाहिए. यह एक अच्छा सुझाव है जिसपर आगे विचार किया जा सकता है.

डॉ. सुशील चन्द्र तिवारी
अपर संचालक, उच्च शिक्षा एवं प्राचार्य
डॉ वा.वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग

छात्राओं का कॉलेज आना-जाना होगा आसान

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नवीन महाविद्यालयों की स्थापना की है. आसपास के 5-10 किलोमीटर की परिधि से विद्यार्थी यहां आते हैं. युवा मितान परिवहन योजना से उनका कालेज आना आसान हो जाएगा. उम्मीद करते हैं कि इससे कैम्पस में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ेगी. वे महाविद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों में शामिल हो पाएंगे जिससे उनका बहुमुखी विकास हो पाएगा.

डॉ आनंद विश्वकर्मा
प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरी, जिला दुर्ग

Valkin's
HEALTHCARE
वाल्किंस डायग्नोस्टिक सेंटर
वाल्किंस स्किन क्लिनिक
2 वर्ष भरोसे और विश्वास का
पूर्ण होने पर वाल्किस परिवार सभी डॉक्टर्स एवं शहर वासियों को तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं।
Awarded by
Hon'ble CM Shri Bhupesh Baghel Ji
HIGH-END MACHINERY & TOP NOTCH SERVICES FOR 1ST TIME IN BHILAI-DURG
डायग्नोस्टिक सुविधाएं
सीटी स्कैन
सोनोग्राफी
ई.सी.जी/ इको
ई ई जी
ब्लड टेस्ट
24x7 सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध
चर्मरोग सुविधाएं
मस्से/स्ट्रेच मार्क्स/वार्ट्स का इलाज
सफ़ेद दाग
झाइयाँ
पीरपी एवं मीसो थेरपी
एंटी एजिंग : बोटॉक्स , केमिकल पील
Q - Switched Laser दुर्ग-भिलाई में पहली बार
Medifacial दुर्ग-भिलाई में पहली बार
US-FDA द्वारा मान्यता प्राप्त उपकरण दुर्ग-भिलाई में पहली बार
टैटू रिमूवल
झाइयां
डी टैनिंग
स्किन ग्लो
पिगमेंटेशन
काले धब्बे का इलाज
कार्बन पील
लेज़र टोनिंग
500/- OFF
Have been staying in US for a long time and did visit multiple dermatologists for the treatment of my nail fungus but to no results. Here they said it cannot be treated! However, got a chance to visit valkins and it was no less than a miracle in just few weeks the nail fungus is gone. Amazing staff, Dr and overall facility is not less than any Dr. Office we would visit in USA. Dr Sukriti is just amazing and best!
-Ankit Senapati
Excellent pathlabs good and cooperative staff, the reporting is instant thats the best part. The doctor was engaging and had the urge not just to perform diagnostics but also to diagnose the problem and give suggestion for treatment and further diagnostic. Overall great experience. Also the staff bhamini was greatly cooperating for all patients and the overall management so as to ensure smooth working of the centre. I guess this is what makes the centre excel in its growth
-Shivam Soni
We came here for sonography. Overall facilities and staff are good. Hospital is neat and clean. Time taken is also very low for services.
Ankur Goyal
डॉ. सुकृति अरोरा
चर्मरोग विशेषज्ञ
(एम.डी. गोल्ड मेडलिस्ट)
GARH 2023
Inauguration of Q switched laser January 2023
Best Dermatologist Award
दुर्ग-भिलाई का मिला प्यार अब है रायपुर का इंतजार
जिस तरह एक बीज धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लेता है उसी तरह आपके अटल स्नेह और विश्वास ने हमेशा वाल्किंस को नई ऊंचाइयां दी है इसके लिए मैं दूसरी वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं
-आशीष अरोरा
ऑनलाइन टेस्ट रिपोर्ट व पेमेंट सुविधा | घर पहुंच ब्लड लेने की सुविधा | US-FDA द्वारा मान्यता प्राप्त उपकरण | एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध
जेल तिराहा के पास, बाफना मंगलम, के बाजु में पदमनाभपुर, दुर्ग
बस स्टैंड के सेंटर, दुर्ग
+91 7880099919
+91 7880090220
दुर्ग-भिलाई -पाटन -धमधा के हजारों मरीजों का भरोसा है वाल्किंस
info@valkins.in
www.valkins.in

वादा है, फिर निभाएंगे

- पहले की तरह किसानों का कर्जा माफ
- इस बार से होगी 20 क्विंटल धान खरीदी
- KG से PG तक पढ़ाई होगी निःशुल्क
- जातिगत जनगणना कराएंगे
- 17.50 लाख गरीब परिवारों को आवास
- लघु वनोपजों पर MSP के अतिरिक्त ₹10
- तेंदूपत्ता संग्राहकों को ₹4000 सालाना बोनस

पंजा का बटन दबाएंगे
कांग्रेस को जिताएंगे

भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

सहेली ज्वेलर्स

RAIPUR | DURG

Presents

खुशियों की सौगात

916 HUID
हॉलमार्क ज्वेलरी

53990/-
प्रति 10 ग्राम

CERTIFIED
हीरों एवं पोल्की के
आभूषणों पर

0%
मेकिंग चार्ज

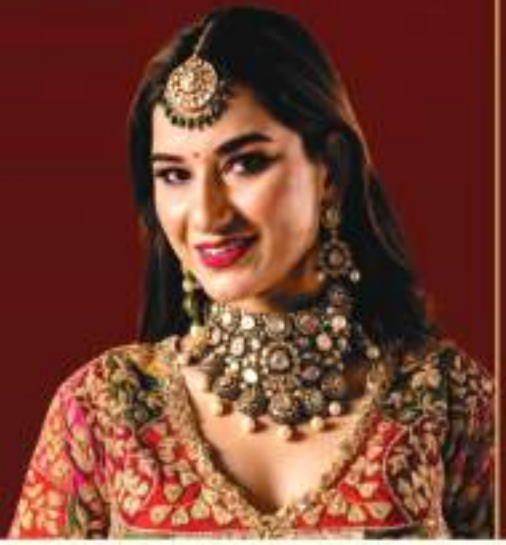

सहेली प्री - बुकिंग ऑफ़र

आज के भाव पर सोने के जेवर की बुकिंग कराएं और भाव कम होने पर कम भाव में और बढ़ने पर बुकिंग भाव में ज़ेवर ले जाएं, दोनों ही स्थिति में फायदा आपका...

THE WORLD'S LARGEST JEWELLERY FESTIVAL
15TH OCT - 22ND NOV

IJSF
INDIA JEWELLERY SHOPPING FESTIVAL 2023

सही शुद्धता - सही सलाह - सही कीमत - सर्वश्रेष्ठ डिजाइन्स

Raipur Sadar Bazaar 0771- 3500084 | Durg Shree Shivam Mall 0788-2321945

VALET PARKING SUNDAY OPEN

*T&C Apply